epaper.dehatsandesh.com

3 डीसी ने वित्तीय समावेशन और बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

5 श्रेयस अयर अस्पाल से डिस्चार्ज, रिकवरी के लिए सिडनी में ही रहेंगे

8 'दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में एहसास करा रहा भारत'

मौसम जम्मू — न्यूनतम 14 — अधिकतम 28

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-269 | जम्मू तवी, रविवार 02 नवम्बर, 2025 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लें संकल्प : थल सेना अध्यक्ष

रीवा, 01 नवंबर। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि आत्मविश्वास, साहस, स्पष्टपता, साथ मिलकर कार्य करने तथा परिवर्तन ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलता दिलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी और हमने आतंकवाद को समाप्त किया। सिंदूर अभियान की लड़ाई सिर्फ सेना ने नहीं बल्कि देशवासियों ने एकता के साथ लड़ी। युवा अपनी ऊर्जा उत्साह और सोच को सही दिशा में लगाकर देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें। अनुशासन और मार्गदर्शन मिलने से हमारे देश की युवा शक्ति भारत को और आगे ले जाने में सहायक होगी।

थल सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी शनिवार को मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आयोजित युवा अभिप्रेरणा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि टीआरएस कॉलेज की फुटबाल टीम को देखकर हम लोग के मन में ईर्षा होती थी। हमारे पूज्य पिता जी कृष्ण द्विवेदी ने भी इस ऐतिहासिक महाविद्यालय में अपनी पढ़ाई की थी। इस महाविद्यालय का मेरी परवरिश में

सिंदूर अभियान की लड़ाई सिर्फ सेना ने नहीं बल्कि देशवासियों ने एकता के साथ लड़ी

महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि रीवा में आपसी भाईचारा और सौहार्द बहुत है। यहां सब लोग मिलकर रहते हैं और उनमें अपनत्व बहुत है। रीवा की भूमि में अनेक वीर सपूत दिये हैं जिनमें कई वीरचक्र, शौर्यचक्र एवं अन्य सम्मान प्राप्त योद्धा शामिल हैं। जनरल द्विवेदी ने सभी को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की बधाई दी।समाचार एजेंसी के अनुसार, जनरल द्विवेदी ने अपने विद्यालय रीवा सैनिक स्कूल में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2025 के दौरान एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा क्योंकि हमने अपने सिद्धांतों और तकनीक की संयुक्त शक्ति से लड़ाई लड़ी। हमने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान में किसी भी निर्दोष नागरिक को नुकसान न पहुँचे। हमने केवल आतंकवादियों और उनके आकाओं को निशाना बनाया।

उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रार्थना के समय कोई कार्रवाई न की जाए। उन्होंने आगे कहा, हमने केवल उन्हीं जगहों पर हमला किया जहाँ आतंकवादी मौजूद थे। हमने निर्दोष नागरिकों या रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपना लक्ष्य हासिल किया और पाकिस्तान को संदेश दिया कि हम उनके जैसे नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में 7 मई को शुरू किया गया था, जिसमें कई नागरिक मारे गए थे।

जम्मू-कश्मीर में स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए एक नए युग की शुरुआत : सिन्हा

श्रीनगर, 1 नवंबर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि स्टार्टअप्स और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए एक नए युग की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को नई गति दे रहे हैं और जम्मू-कश्मीर के निवेशकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

समाचार एजेंसी के अनुसार, यहाँ पहले आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, उद्यमी, निवेशक और नीति-निर्माता आज एक ही स्थान पर एकत्रित हुए हैं और मुझे विश्वास है कि स्टार्टअप्स और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए एक नए युग की शुरुआत हो गई है।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ जिन सुधारों को नई गति दे रहे हैं, उनका सीधा लाभ जम्मू-कश्मीर के निवेशकों को मिलेगा।

उपराज्यपाल ने कहा, हमें मौजूदा क्षमताओं, बेहतर बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाना चाहिए, जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों

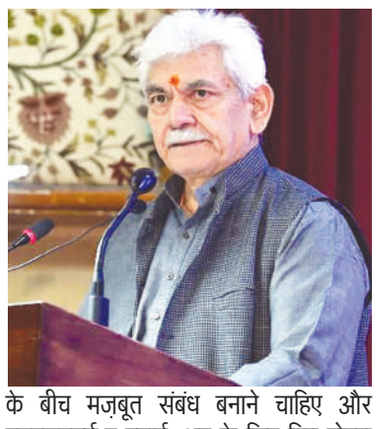

के बीच मज़बूत संबंध बनाने चाहिए और एमएसएमई व स्टार्ट-अप के लिए वित्त पोषण की कमी को पूरा करना चाहिए।

उन्होंने केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल), जम्मू-कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (जेकेईडीआई) और जम्मू-कश्मीर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को जम्मू-कश्मीर के स्टार्ट-अप और एमएसएमई उद्यमियों को वेंचर कैपिटल फर्मों और संस्थागत निवेशकों से जोड़ने की इस ऐतिहासिक पहल के लिए बधाई दी।

उपराज्यपाल ने वेंचर कैपिटलिस्ट (वीसी) और निवेशकों से व्यक्तिगत उद्यमियों की क्षमताओं, जम्मू-कश्मीर की क्षमता और व्यावसायिक उद्यम का पूरी संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी के साथ आकलन करने को कहा। उपराज्यपाल ने वेंचर कैपिटलिस्टों और निवेशकों से कहा, जम्मू-कश्मीर का औद्योगिक विकास, स्टार्ट-अप और एमएसएमई का कायाकल्प केवल एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। यह राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य है।

जम्मू-कश्मीर के एमएसएमई और स्टार्ट-अप का तेज़ी से विकास निवेशकों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के युवा और उभरते उद्यमियों को बेहतर संसाधन और अवसर प्रदान करने का भी आह्वान किया।उन्होंने कहा कि यह आयोजन एसआरआई फंड के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और उद्यमियों को एमएसएमई के लिए वित्त पोषण की कमी को पूरा करने में इसकी सक्रिय भूमिका के बारे में सूचित करेगा।

खबर संक्षेप

6 नवंबर तक किरायेदार और कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य : डीएम

जम्मू तवी, 1 नवंबर। जम्मू में अधिकारियों ने सभी मकान मालिकों, संपत्ति मालिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अपने किरायेदारों, घरेलू सहायकों और कर्मचारियों का विवरण सात दिनों के भीतर स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

जिला मजिस्ट्रेट राकेश मिन्हास ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत शुक्रवार को जारी यह आदेश, जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें इस तरह के सत्यापन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

यह आदेश स्थानांतरण कार्यालयों के फिर से खुलने से कुछ दिन पहले आया है, जो 31 अक्टूबर को श्रीनगर में बंद कर दिए गए थे और दरबार स्थानांतरण की पुरानी प्रथा के अनुसार 3 नवंबर को यहाँ फिर से खुलने वाले हैं।

निर्देश के अनुसार, सभी संपत्ति मालिकों, ठेकेदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रमुखों को अपने किरायेदारों और कर्मचारियों का विवरण एक घोषणा पत्र के माध्यम से, मालिक और किरायेदार/कर्मचारी दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित एसएचओ को प्रस्तुत करना होगा।

निर्देश में कहा गया है कि जिन लोगों ने आदेश जारी होने से पहले ही परिसर किराए पर दे दिया है या कामगारों को काम पर रखा है, उन्हें 6 नवंबर तक विवरण प्रस्तुत करना होगा। जो लोग भविष्य में ऐसा करेंगे, उन्हें भी सात दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर एसएचओ को सूचित करना होगा।

आदेश में जम्मू जिले के प्रत्येक पुलिस थाने को किरायेदारों और कर्मचारियों के सत्यापन रिकॉर्ड के लिए एक अलग रजिस्टर रखने का निर्देश दिया गया है।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को काम पर रखने, साथ ही संपत्ति को पेइंग गेस्ट और किरायेदारों को किराए पर देने या उप-किराए पर देने की सभी व्यवस्थाएँ इस आदेश के अंतर्गत आएंगी।

4 और 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना

श्रीनगर, 1 नवंबर । मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने जम्मू और कश्मीर के लिए मौसम पूर्वानुमान और सलाह जारी की है जिसमें अगले कुछ दिनों में मुख्यत: शुष्क मौसम रहने और उसके बाद आगामी सप्ताह केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 3 नवंबर तक जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। हालांकि 4 और 5 नवंबर को क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है और 4 नवंबर की शाम और रात के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी होने की संभावना है जो 5 नवंबर की सुबह या दोपहर तक जारी रहेगी। पूर्वानुमान में आगे कहा गया है कि 6 से 13 नवंबर तक फिर से मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा और कोई महत्वपूर्ण वर्षा होने की उम्मीद नहीं है। अपने परामर्श में मौसम विभाग ने आगाह किया है कि 4 नवंबर की शाम को कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज़ हवाएँ चल सकती हैं।

दरबार मूव के तहत श्रीनगर के सभी सरकारी कार्यालय छह माह के लिए हुए बंद

जम्मू,, 1 नवंबर । जम्मू-कश्मीर प्रशासन के दरबार मूव कार्यक्रम के तहत ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में पांच दिन काम करने वाले सभी मूव कार्यालय शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को कार्यालय समय के बाद अगले छह महीनों के लिए बंद हो गए। वहीं छह दिन काम करने वाले कार्यालय शनिवार, 1 नवंबर 2025 को बंद होंगे। इसके साथ ही अधिकारी और कर्मचारी 1 व 2 नवंबर को श्रीनगर से जम्मू की ओर प्रस्थान करेंगे। हालांकि, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले गृह विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है और वे दोनों स्थानों — श्रीनगर और जम्मू — में एक साथ कार्य करते रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन अब लगभग पूरी तरह ई-ऑफिस प्रणाली में परिवर्तित हो चुका है, जिससे फाइलों और अभिलेखों के भौतिक स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं रही। केवल कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ही भौतिक रूप से स्थानांतरित किए जाएंगे, जबकि शेष डेटा पेन ड्राइव्स या डिजिटल माध्यम से भेजा जाएगा। ई-ऑफिस प्रणाली 2021 में शुरू की गई थी, और 2023 तक प्रशासन पूरी तरह डिजिटल हो गया। इसके बाद ऑनलाइन सेवाओं की

निगरानी के लिए छह सदस्यीय समन्वय सेल का गठन किया गया, जो सभी जिलों में ई-सेवाओं की प्रगति पर नज़र रखता है।

यात्रा और सुरक्षा व्यवस्थाएँ- दरबार मूव कर्मचारियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए जेकेआरटीसी की बसों और आधिकारिक काफिले की निगरानी हेतु ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतज़ाम किए हैं। आईजीपी ट्रैफिक विवेक गुप्ता के अनुसार, 1 और 2 नवंबर को श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर केवल डाउनवर्ड ट्रैफिक (श्रीनगर से जम्मू की ओर) को अनुमति दी जाएगी। इन दो दिनों के दौरान जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले भारी वाहनों, सेना, अर्धसैनिक बलों और सरकारी काफिलों को प्रतिबंधित किया गया है ताकि मार्ग पर भीड़भाड़ और असुविधा से बचा जा सके। जम्मू में मूव कर्मचारियों के ठहराव के लिए बी.सी. रोड, सरवाल, अहाता अमर सिंह (पंजतीर्थी) और मुठी सहित कई स्थलों पर सरकारी क्वार्टरों का नवीनीकरण किया गया है।

अदालत ने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के लिए पूर्व ग्रामीण विकास इंजीनियर को सात साल की सजा सुनाई

पुलवामा, 23 अक्टूबर। भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायाधीश, पुलवामा, डॉ. नूर मोहम्मद मीर ने ग्रामीण विकास विभाग के एक पूर्व कनिष्ठ अभियंता को 25 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी सेवा अभिलेखों में छेड़छाड़ करने का दोषी ठहराया और उसे सात की साल जेल की सजा सुनाई। तत्कालीन सतर्कता संगठन कश्मीर (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) द्वारा एफआईआर संख्या 24/2000 के तहत दर्ज किया गया यह मामला, आरोपी की सेवा अवधि को अवैध रूप से बढ़ाने के लिए उसकी सेवा पुस्तिका और जन्मतिथि में हेरफेर करने से संबंधित था। दो दशकों से ज्यादा समय तक चली विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे सात साल की कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3,52,760 का जुर्माना भी लगाया।

गुलदाउदी उद्यान शरद ऋतु में घाटी आने वाले पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत आकर्षण का केंद्र होगा: फारूक

श्रीनगर, 1 नवंबर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि हाल ही में खुला गुलदाउदी उद्यान शरद ऋतु में घाटी आने वाले पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत आकर्षण का केंद्र होगा।

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नेहरू मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन में घाटी के पहले गुलदाउदी उद्यान जिसे बाग-ए-गुल-ए-दाऊद के नाम से भी जाना जाता है का दौरा किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 25 अक्टूबर को इस उद्यान का जनता के लिए उद्घाटन किया था। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के सामने कहा कि यह एक सुंदर उद्यान है। यहाँ लगे कोई भी फूल आयातित नहीं हैं, इन्हें यहीं उगाया गया है। मुझे लगता है कि ट्यूलिप गार्डन के बाद यह वह उद्यान होगा जिसे कम रखरखाव की आवश्यकता होगी उन्होंने कहा कि घाटी में पतझड़ के

मौसम में दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है लेकिन यह उद्यान देश के लोगों के लिए सबसे सुंदर आकर्षण है। नेकां अध्यक्ष ने कहा कि पर्यटकों को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि यह उद्यान कितना सुंदर है और यहाँ कितने रंग-बिरंगे फूल उगाए गए हैं। उन्होंने फूलों को खूबसूरती और आकर्षक ढंग से सजाने के लिए उद्यान में काम करने वाले माली सहित, पुष्प कृषि विभाग को बधाई दी।

दरबार मूव को खत्म करने के फैसले से जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय संतुलन और प्रशासनिक एकता को गहरा आघात पहुँचा : उमर

श्रीनगर, 1 नवंबर । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को उपराज्यपाल प्रशासन पर सदियों पुरानी दरबार मूव को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय संतुलन और प्रशासनिक एकता को गहरा आघात पहुँचा है। श्रीनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उमर ने लोगों को याद दिलाया कि उनकी सरकार ने ही इस अर्धवार्षिक प्रथा को बहाल किया था और इसे जम्मू और श्रीनगर के बीच समझ का पुल बताया। उमर ने पूछा कि दरबार मूव को बंद करने की क्या मजबूरी थी। यह परंपरा शेख अब्दुल्ला या मेरी विरासत नहीं है। यह 1947 से पहले, आज़ादी से भी पहले से मौजूद थी। जब मैंने देखा कि जम्मू शहर के साथ अन्याय हुआ है तो मैंने दरबार मूव को फिर से स्थापित किया

और उस अन्याय को दूर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दरबार मूव को रद्द करने वालों ने क्षेत्रों को भावनात्मक और आर्थिक रूप से विभाजित कर दिया। उन्होंने कहा कि दरबार मूव राजनीति का नहीं बल्कि एकता का प्रतीक था। इसने सुनिश्चित किया कि दोनों राजधानियाँ प्रशासनिक महत्व और विकास साझा करें। इसे समाप्त करके उन्होंने उस बंधन को तोड़ दिया।उमर ने स्पष्ट किया कि दरबार मूव को बहाल करने का उनका निर्णय निष्पक्षता पर आधारित था न कि राजनीतिक लाभ पर। उन्होंने कहा कि अगर मुझे धर्म या क्षेत्र के आधार पर फैसला करना होता तो मैं जम्मू में अपना कार्यालय नहीं खोलता, मैंने वहाँ से चुनाव भी नहीं जीता। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं न्याय में विश्वास करता हूँ, विभाजन में नहीं। श्रीनगर के विकास में ठहराव की ओर ध्यान दिलाते हुए उमर ने एक के बाद एक सरकारों पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद अन्याय और उपेक्षा का बोलबाला रहा। अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो हम सारा दिन यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी 2015 के बाद श्रीनगर को कौन सी नई परियोजना मिली सौंदर्यीकरण, बुनियादी ढाँचे, यातायात प्रबंधन या बाढ़ नियंत्रण में। कुछ भी नहीं है।

भाजपा-पीडीपी जो नहीं कर पाईं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 साल में कर दिखाएगी : उपमुख्यमंत्री

श्रीनगर, 1 नवंबर। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने शनिवार को यह दावा करते हुए कि भाजपा और पीडीपी जो काम 11 साल में नहीं कर पाईं, उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 साल में पूरा कर देगी, निर्वाचित सरकार के अधिकारों पर सवाल उठाया। समाचार एजेंसी के अनुसार, बुलेवार्ड रोड के चौड़ीकरण की आधारशिला रखने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और इसे वर्षों पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए था। कल, मुख्यमंत्री ने कमरवारी पुल का उद्घाटन किया और आज, हमने बुलेवार्ड चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया है। ये परियोजनाएँ 11 साल से ज्यादा समय से लंबित थीं। डलगेट कश्मीर की एक वैश्विक पहचान है और यह सड़क चौड़ीकरण बेहद ज़रूरी था। ठेकेदारों को समय सीमा के भीतर काम

> सरकार को पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए

पूरा करने का निर्देश दिया गया है, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि सनत नगर और कमरवारी समेत कई पुल और सड़कें सालों से अधूरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा, जो काम भाजपा और पीडीपी 11 साल में पूरा नहीं कर पाईं, उसे हम पाँच साल में पूरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार को विरासत में बहुत बड़ा काम लंबित मिला है और वह नई प्रतिबद्धताओं के साथ लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि वे पिछली सरकारों के दुष्प्रचार के बजाय सरकार की ईमानदारी और विकास कार्यों को उजागर करें। राज्य का दर्जा और शासन संबंधी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचित सरकार को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, उपराज्यपाल साहब को लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। अगर एक निर्वाचित सरकार को प्रोटोकॉल भी नहीं मिलता और अधिकारी कैबिनेट के साथ खड़े नहीं होते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास पूरे अधिकार हैं? फाइलें और प्रशासन अभी भी नियंत्रित हैं।

कैट श्रीनगर ने 2008 से एक आकस्मिक कर्मचारी को पूर्वव्यापी रूप से नियमित करने का दिया आदेश

श्रीनगर, 1 नवंबर। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की श्रीनगर पीठ ने जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह एक लंबे समय से कार्यरत आकस्मिक कर्मचारी को 2008 के एसआरओ 308 के तहत 16 अक्टूबर, 2008 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में पूर्वव्यापी रूप से नियमित करे। साथ ही उसकी आकस्मिक सेवा का 50 प्रतिशत अर्हक पेंशन लाभों में शामिल करने का भी आदेश दिया है। यह आदेश डी.एस. माहरा (सदस्य-न्यायिक) द्वारा बांदीपोरा के बरजुल्ला पंजीगाम निवासी मोहम्मद अमीन बाबा द्वारा दायर ओ.ए. संख्या 1775/2021 पर सुनाया गया। आवेदक का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बी.ए. टाक ने किया। ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों के अनुसार आवेदक 5 जुलाई, 1992 से ही आकस्मिक आधार पर नियुक्त था और लगभग तीन दशकों तक लगातार और संतोषजनक ढंग से सेवा करता रहा। एसआरओ 308 के तहत सभी मानदंडों को पूरा करने के बावजूद उसका नियमितीकरण 4 सितंबर, 2020 तक स्थगित कर दिया गया जिससे उसे वैध मौद्रिक और सेवा लाभों से वंचित कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि नियमितीकरण में देरी पूरी तरह से प्रशासनिक थी और आवेदक के कारण नहीं थी। इसने पाया कि 16 अक्टूबर, 2008 को एसआरओ 308 अधिसूचित होने के बाद प्रतिवादी उस तिथि से सभी पात्र आकस्मिक-वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए विचार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। ज़रीफ़ा बेगम के मामले में दिए गए पिछले फ़ैसले का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने दोहराया कि आकस्मिक वेतन या कार्यभारित कर्मचारी जिसे बाद में नियमित प्रतिष्ठान में लाया जाता है, ऐसी सेवा के 50 प्रतिशत को पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिनने का हकदार है और यह नियमितीकरण लागू एसआरओ के तहत पात्रता की तिथि से प्रभावी होना चाहिए। आवेदन स्वीकार करते हुए न्यायाधिकरण ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे आवेदक को 16 अक्टूबर, 2008 से नियमित मानें, उसके वेतन और वरिष्ठता को तदनुसार निर्धारित करें, 1992 से 2008 तक उसकी आकस्मिक वेतन वाली सेवा के 50 प्रतिशत को पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिनें और सभी परिणामी पेंशन लाभ जारी करें।

एसआईए ने श्रीनगर में नार्को टेरर मॉड्यूल के मुख्य संचालक को किया गिरफ्तार

श्रीनगर, 1 नवंबर । राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शुक्रवार को श्रीनगर शहर के बेमिना इलाके से लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल के एक प्रमुख संचालक को गिरफ्तार किया है।

एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि ताड़ करनाह कुपवाड़ा निवासी बशारत अली पिछले 03 वर्षों से एसआईए कश्मीर की एफआईआर संख्या 19/2022 के तहत गिरफ्तारी से बच रहा था। कई वर्षों के अथक प्रयासों के बाद आज उसे एसआईए कश्मीर की एक विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया। यह मामला लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान प्रायोजित नार्को-टेरर मॉड्यूल से संबंधित है, जो करनाह सेक्टर में सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में शामिल था। नशीले पदार्थों की बिक्री से प्राप्त आय का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। बशारत इस मामले में गिरफ्तार होने वाला चौथा घोषित भगोड़ा है और एसआईए को उसकी गिरफ्तारी से मामले के और भी तार जुड़ने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि इस साल एसआईए कश्मीर ने नार्को-टेररिज्म के खतरे को खत्म करने के अपने प्रयास में कई सफल अभियान चलाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादी संगठनों के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है

सुशासन देने के लिए कहने पर मुख्यमंत्री भड़क उठते हैं : विपक्ष के नेता

जम्मू, 1 नवंबर। विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुशासन पीछे छूट गया है और वह (उमर) ज़मीनी स्तर पर अपनी नाकामी के लिए हर दिन बेकार बहाने बना रहे हैं। शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा न करने के लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। शर्मा ने पूछा, मुख्यमंत्री और उनकी सरकार बयानबाज़ी के पीछे नहीं छिप सकते। आपने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लड़ा था। यह बात सभी जानते हैं। आपके पास काम करने का पूरा अधिकार और अधिकार है। आपको लोगों के लिए काम करना चाहिए। आपको इससे परेशानी क्यों होती है? उन्होंने कहा कि जब भी कोई सरकार को अपना काम करने के लिए कहता है, तो वह गुस्सा हो जाती है और रक्षात्मक हो जाती है। शर्मा ने कहा, वे हमेशा गुस्सा हो जाते हैं। वे कभी कोई तर्क या तकनीकी स्पष्टीकरण नहीं देते। वे बस गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि वे खुद को बेनकाब

महसूस करते हैं। जब भी उन्हें उनके वादों या कर्तव्यों की याद दिलाई जाती है, तो उन्हें परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहलगाम आतंकी हमले को शासन की विफलता का बहाना नहीं बना सकते। शर्मा ने कहा, उस बर्बर कृत्य के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा मिल चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ हालात बेहतर हैं। लेकिन अगर आपको बिजली की कमी, बढ़ते भ्रष्टाचार या गैस सिलेंडर की कमी से लोगों को परेशान करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, तो पहलगाम नरसंहार को आड़ के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे।

ये टिप्स अपनाएंगे तो हर कोई हो जाएगा आपके पर्सनैलिटी का फैन

आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या आपको लगता है अच्छे कपड़े पहनना या अंग्रेजी बोलना या फिर लोगों से मिलना पर्सनालिटी डेवलपमेंट है? तो जवाब मिलेगा नहीं। केवल यह शब्द मिलकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य नहीं करते बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। आइए कुछ टिप्स के विषय में जान लेते हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्य करते हैं।

कॉन्फिडेंस बनाएं रखें

किसी भी कार्य को आसान करने का सबसे पहला मंत्र है कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी भी काम करते समय कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। कॉन्फिडेंस से भरे लोगों से हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं को खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रयास करें। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू करें और नए-नए विषयों को एक्सप्लोर करना शुरू करें।

हर विषय पर ओपिनियन बनाने का प्रयास करें

अगर आप खुद को दूसरों से अलग बनाना चाहते हैं तो प्रयास करें कि आप हर विषय में अपना एक ओपिनियन बनाएं ताकि कभी आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें। लेकिन ध्यान रखें कि बिना मांगे ओपिनियन देने से आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिव रूप में भी प्रदर्शित कर सकता है।

अच्छे श्रोता बनें

हम हमेशा उन लोगों को दूसरे के मुकाबले अधिक तवज्जो देते हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अच्छा श्रोता होना एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों को सुनना शुरू करें और एक अच्छा श्रोता बनने का प्रयास करें।

बॉडी लैंग्वेज को सुधारें

पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बॉडी लैंग्वेज पर काम करना बेहद जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके बारे में कई बातें बताती है। आपके चलने, बैठने, बातें करने या खाने के तरीके सहित सब कुछ आपके आस-पास के लोगों पर प्रभाव डालता है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज एक अच्छी पर्सनालिटी की तरफ कार्य करती है।

इन तरीकों से खुद को कर सकते हैं जॉब में मोटिवेट

आज के दौर में जब जॉब की इतनी बहुतायत है, वहीं लोगों में उस जॉब को पानी के लिए जरूरी स्किल्स की कमी है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोगों में अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज तो है, पर कहीं न कहीं कई ऐसी वजहें होती है जो उन्हें अपने फील्ड में बहुत अच्छा करने से रोकती हैं। ये लोग डिमोटिवेट होते हैं। तो आइए जानते हैं खुद को मोटिवेट कैसे किया जाए

- खुद को शांत रखना सीखिए। ऐसा करने से आपका दिमाग ठीक तरीके से काम करता है और आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।
- ऐसे विचारों को माइंड में कभी न लाएं जो आपके किसी अच्छे काम को प्रभावित करें। हम अक्सर दूसरों से राय लेने में नहीं चूकते। जब कुछ नया करने जा रहे होते हैं। अब यह निर्भर करता है कि जिससे आपने राय ली है, वह आपका हित चाहने वाला है या नहीं, तो तुरंत किसी की बात को न मानें। उस पर विचार करें। उसके बाद ही कोई कदम उठाएं।
- अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हों तो अपने डर पर विजय हासिल करें। कॉन्फिडेंट रहिए, डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वालों को भी अपनी ही तरह एक आम इंसान ही समझें। सोचिए कि अगर आप किसी ऊंची पोस्ट पर होते हैं तो सब आपके हाथ में होता।
- जब आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हों तो ये सोचिए कि आप कई इंटरव्यू दे चुके हैं। भले ही यह आपका पहला इंटरव्यू रहो। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अपनी सक्सेस को हमेशा अपने साथ लेकर चलें। यह कभी न सोचें कि अगर सिलेक्शन न हुआ तो।
- जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अपनी कमियों को खुद पर हावी न होने दें। जो भी स्किल या नॉलेज आपके पास है उसे बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करें।
- साफ-सुथरी बात सभी को अच्छी लगती है। आपका बात करने का अंदाज विनम्र होना चाहिए। साथ ही स्पष्ट और कम शब्दों में होना चाहिए।

बहुत बड़ा है एविएशन इंडस्ट्री का दायरा

अगर आप भी एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को पायलट व केबिन क्रू बनने के काबिल नहीं पाते, तो निराश मत हो, क्योंकि इसके अलावा भी अब इस सेक्टर में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। ज्यादातर लोग एविएशन क्षेत्र के दायरे को पायलट, एयर होस्टेज व केबिन क्रू तक सीमित कर देते हैं, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। आप इस इंडस्ट्री में एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, फ्लाइट इंजीनियर, एयर टिकटिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, एयर कार्गो मैनेजमेंट, मीटिरियोलॉजिस्ट आदि जॉब प्रोफाइल पर भी कार्य कर सकते हैं।

ग्राउंड स्टाफ

एविएशन इंडस्ट्री में ग्राउंड स्टाफ महत्वपूर्ण होते हैं। इनका कार्य एयरपोर्ट की साफ-सफाई के साथ उसके रखरखाव करना है। एयरपोर्ट पर प्लेन जब उतर जाता है, तो उसके बाद पैसेंजरों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर सामान ढुलाई और माल स्टॉक का कार्य भी ग्राउंड स्टाफ को ही कराना होता है। ग्राउंड स्टाफ की एयरपोर्ट पर अलग-अलग कार्य की जिम्मेदारी संभालते हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में करियर बनाने के लिए आप एयरपोर्ट मैनेजमेंट से रीलेटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर लेवल के कोर्स कर इस फील्ड में प्रवेश कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप इस सेक्टर में प्रवेश कर सकते हैं।

एयर कार्गो मैनेजमेंट

इस जॉब प्रोफाइल पर रहकर करियर बनाने के लिए आपको डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एयर कार्गो मैनेजमेंट कोर्स करना होगा। जिसमें आप एविएशन हिस्ट्री एवं जियोग्राफी के अतिरिक्त कार्गो लॉ, कस्टम्स रूल्स, वेयरहाउसिंग, एयरक्राफ्ट लिमिटेशन व लोडिंग कैपेसिटी, क्लीयरेंस प्रोसिजर, क्लेम रूल्स, बीमा और फ्री ट्रेड जोन जैसे विषयों से रूबरू होंगे। इस क्षेत्र में भी प्रवेश के लिए आपको न्यूनतम 12वीं की शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। यह कोर्स आपको 6 माह से 1 वर्ष तक का होता है।

एयर टिकटिंग

एविएशन के एयर टिकटिंग में करियर बनाने के लिए न्यूनतम 12वीं की शैक्षणिक योग्यता के साथ 18 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए। न्यूनतम 6 माह से 9 माह तक की अवधि वाले कोर्स डिप्लोमा इन एयर टिकटिंग एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में ट्रैवल एजेंसी बिजेनस, वर्ल्ड टाइम जोन, एयरपोर्ट व एयरलाइन कोड्स, पेमेंट मोड्स, फॉरेन करेंसी, पासपोर्ट व वीजा आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

फ्लाइट इंजीनियर

एविएशन के क्षेत्र में फ्लाइट इंजीनियर का कार्य बहुत अहम होता है। प्लेन के सभी पुर्जों की जांच करना इनकी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल, एयरोनॉटिकल या कम्प्यूटर में से किसी एक में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आपके पास फ्लाइट इंजीनियर का ग्राउंड पाठ्यक्रम या एयर क्राफ्ट इंजीनियर लाइसेंस या सीपीएल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने 12वीं विज्ञान विषयों से पास की हो और आपकी उम्र तीस साल से ज्यादा ना हो, तो आप इसमें करियर बना सकते हैं।

एयर ट्रैफिक कंटोलर्स

एविएशन के क्षेत्र में यह एक और महत्वपूर्ण जॉब प्रोफाइल है। एयरपोर्ट पर बने टॉवर से एयर ट्रैफिक कंटोलर्स हर वक्त प्लेन की उड़ानों पर नजर रखते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के आपको रेडियो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग बीटेक या डिप्लोमा करना होगा।

मीटिरियोलॉजिस्ट

एविएशन में मीटिरियोलॉजिस्ट का भी बड़ा रोल होता है। इसमे कैरियर बनाने के लिए अगर आपके पास मौसम विज्ञान, भौतिक, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गणित और दूरसंचार में ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई करने योग्य हैं।

टूर एंड ट्रैवल

अगर आप एविशन के क्षेत्र में रहकर अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं तो टूर एंड ट्रैवल आपके लिए बेस्ट होगा, इस क्षेत्र में आपको बहुत काम मिलेगा। इस क्षेत्र में आने के लिए आप 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर तीन वर्षीय बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं।

यहां से कर सकते हैं कोर्स

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, नई दिल्ली
- फ्रांकलिन एविएशन एकेडमी, दिल्ली
- विंग्स कॉलेज ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी, पुणे
- ए जे एविएशन एकेडमी, मुम्बई
- राजीव गांधी एविएशन एकेडमी, हैदराबाद
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स साइंस, जमशेदपुर
- हिंदुस्तान एविएशन एकेडमी, बंगलूरू

क्या है आर्कियोलॉजी? किस कोर्स के बाद मिलेगी हाई सैलरी

अगर आप इतिहास से लगाव रखते हैं और आप रोमांच के साथ रहस्य से पर्द उठाना चाहते हैं। साथ ही आपमें ऐतिहासिक चीजों को जानने और उनके बारे में तरह-तरह की जानकारियां पता करने की इच्छा है तो आप आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। इतिहास और भूगोल के रहस्यों से पटे भारत में इसके अच्छे हड़प्पा सभ्यता के बाद से भारत में ऐतिहासिक खोज न के बराबर हुई है और फिलहाल इतिहास संबंधित खोज को लेकर एक बड़ा वैक्यूम यहां बना हुआ है, जो बड़े आइडियाज और क्रिएटिविटी का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही दुनियाभर में शोध के लिए आर्कियोलॉजी के विद्यार्थियों की मांग है।

क्या है आर्कियोलॉजी

पृथ्वी पर छपी पुरानी सभ्यता और संस्कृति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना व उनकी खोज करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजी में उस इतिहास के बारे में यह जानने की कोशिश की जाती है कि पुरानी सभ्यताओं में लोगों का रहन- सहन कैसा था। किस तरह की वस्तुओं का वो इस्तेमाल करते थे। अनुमानों लेकर तत्कालीन समाज और परिवेश के आकलन का काम भी एक आर्कियोलॉजिस्ट को करना होता है। साथ ही वह कार्बन डेटिंग और समय गणना का काम भी करता है। सभी तरह के ऐतिहासिक वस्तु या सभ्यता के वर्तमान से जुड़ाव और विकास के क्रम को निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी एक आर्कियोलॉजिस्ट की होती है।

किस तरह का होता है कोर्स

अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको 12वीं की परीक्षा इतिहास विषय के साथ पास करनी होगी। इसके बाद आप आर्कियोलॉजी में डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर और पीएचडी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें प्रवेश के लिए अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इससे जुड़े कोर्स देश के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों से किए जा सकते हैं। मास्टर इन कंजर्वेशनए प्रिजरवेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट और मास्टर इन आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट जैसे कोर्स इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की सीढ़ी हो सकते हैं। इसके अलावा आप हिस्टॉरिकल आर्कियोलॉजी, जिओ आर्कियोलॉजी, आर्कियोबॉटनी, क्रॉनोलॉजिकल, एथनोआर्कियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल ऑर्कियोलॉजी, आर्कियोमेट्री जैसे कोर्स भी कर सकते हैं।

जरूरी योग्यता

एक बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट अथवा म्यूजियम प्रोफेशनल बनने के लिए प्लीस्टोसीन पीरियड अथवा क्लासिकल लैंग्वेजए मसलन पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, अरेबियन भाषाओं में से किसी की जानकारी आपको कामयाबी की राह पर आगे ले जा सकती है। आर्कियोलॉजी न केवल दिलचस्प विषय है बल्कि इसमें कार्य करने वाले प्रोफशनल्स के लिए चुनौतियों में भरा क्षेत्र भी है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी विश्लेषणात्मक क्षमताए तार्किक सोचए कार्य के प्रति समर्पण जैसे महत्वपूर्ण गुण जरूर होने चाहिए। कला की समझ और उसकी पहचान भी आपको औरों से बेहतर बनाने में मदद करेगा।

यहां से कर सकते है कोर्स

- आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
- बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
- दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट
- कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी

जॉब ऑप्शन क्या हैं

आर्कियोलॉजी में कोर्स पूरा करने के बाद आपको जॉब के कई ऑप्शन मिलेंगे। जिनमें मुख्य रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली, राज्यों में स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, विभिन्न संग्रहालय, एनजीओ और यूनिवर्सिटी, विदेश मंत्रालय का हिस्टोरिकल विभाग, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन विभाग, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आदि।

सैलरी व संभावनाएं

यह ऐक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको रोमांच और रहस्य के साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। अगर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप 30 से 50 हजार रूपये प्रतिमाह की जॉब आसानी से पा सकते हैं, जो अनुभव व आपकी खोज के साथ जॉब प्रोफाइल के हिसाब से लाखों रूपये की सैलरी पा सकते हैं।

इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करियर बनाना है बेहद आसान

इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पिछले कुछ सालों से लगातार तेजी से विस्तार कर रही है, जिसके चलते एक्चुरियल प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी बढ़ गया है। अगर आप भी इंश्योरेंस सेक्टर में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो यह समय काफी अच्छा है, खास कर कोरोना के बाद इंश्योरेंस के हेल्थ सेक्टर में बूस्ट आया है। आज के समय लगभग हर परिस्थिति से निपटने के लिए बीमा कंपनियों के पास पॉलिसी हैं। जीवन बीमा, यात्रा बीमा, वाहन बीमा, स्वस्थ्य बीमा तथा गृह बीमा इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित हैं।

एजुकेशन

इस क्षेत्र में जाने के लिए आप 12वीं व ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन विषय का पूरा ज्ञान लेने के लिए एक्चुरियल साइंस से संबंधित कोर्सेस में स्नातक डिग्री के लिए मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स में 55 प्रतिशत अंकों के साथ बारहवीं पास होना आवश्यक है जबकि पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मैथ्स-स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स सब्जेक्ट से स्नातक जरूरी है। स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुरी प्रोफेशनल बनने के लिए स्टूडेंट्स को एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया का फेलो मेंबर होना जरूरी है। यह संस्थान इसमें कोर्सेस भी कराता है।

इंश्योरेंस का कार्य क्षेत्र

इसके लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस और फाइनेंस इंडस्ट्री में जोखिम का अनुमान लगाते हैं। एक्चुरियल प्रोफेशनल्स यह हिसाब लगाते हैं कि किसी पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम के तौर पर कितनी राशि का भुगतान करना होगा या किसी कंपनी को पेंशन या रिटर्न पर कितना खर्च करना होगा। प्रोफेशनल का काम अचानक घटी घटना के आर्थिक प्रभाव का अंदाजा लगाने का भी होता है। आज इस क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स को इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बैकबोन भी कहा जाने लगा है।

स्किल व एलिजिबिलिटी

इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए खुद को अपडेट रखना जरूरी है। खुद में लोगों की परेशानी को समझने, नई तकनीक सीखने में हिचकिचाहट न होने, कम्युनिकेशन के साथ मैथ और स्टेटिस्टिक्स पर पकड़ मजबूत रखने जैसे स्किल का होना जरूरी है। अपनी योग्यता के आधार पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड असिस्टेंटए डेवलपमेंट ऑफिसरए इंश्योरेंस एजेंटए इंश्योरेंस सर्वेयरए एक्चुरी मैनेजरए रिस्क मैनेजर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं।

जॉब्स के अवसर

अगर आपके पास एक्चुरियल साइंस की डिग्री है तो आपके लिए इन दिनों नौकरियों के लिए कई रास्ते खुल गए हैं। इंश्योरेंस, बैंकिंग, बीपीओ-केपीओ, आईटी सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनियों, फाइनेंशियल कंपनियों आदि में इनके लिए अच्छे मौके होते हैं। दूसरी तरफ, बीपीओ कंपनी में भी जोखिम के बारे में विश्लेषण करने के लिए बड़े पैमाने पर एक्चुरियल प्रोफेशनल्स की हायरिंग होती है। बीपीओ में काम करने वाले एक्चुरी प्रोफेशनल्स की सैलरी भी आम बीपीओ एंप्लॉइज की तुलना में दो से तीन गुना अधिक होती है।

भारत में संभावनाएं इसलिए भी अधिक हैं, क्योंकि वैश्विक ग्राहकों को कम संसाधन और न्यूनतम लागत में अच्छी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। वहीं एक्चुरियल प्रोफेशनल्स की डिमांड सरकारी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में ही नहीं, बल्कि टेरिफ एडवाइजरी कमिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, फाइनेंशियल एनालिसिस फर्म में भी है।

सैलेरी

इस क्षेत्र में आप फ्रेशर के तौर पर प्रतिमाह 20 से 30 हजार रुपये तक आसानी से पा सकते हैं। वहीं अनुभव व समय के साथ किसी उच्च पद पर पहुंचने पर आप 1 लाख रुपये का मासिक वेतनमान भी ले सकते हैं। यदि आपने किसी टॉप कॉलेज से एमबीए इन इंश्योरेंस किया है तो आप अपनी फर्स्ट जॉब में ही ज्यादा बेहतर वेतनमान की अपेक्षा कर सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

कालेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय
एकेडमी ऑफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट, दिल्ली
बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, दिल्ल
इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुंबई
एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे
एमिटी स्कूल ऑफ इंश्योरेंस एंड एक्चुरियल साइंस, नोएडा

स्वामी, प्रकाशक एवं मुंद्रक – नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड़, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-बी, फेस-2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गंग्याल, जम्मू से मुद्रित। संपादक– नीलम सिंह गिल। फोन नंबर : (95) 191-2574109, 2548103 RNI Regd. No: JKBIL/2004/13144 Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com

माउंट लिटेरा जी स्कूल कठुआ में अलंकरण समारोह 2025-26 आयोजित

कठुआ, 01 नवंबर (हि.स.)। माउंट लिटेरा जी स्कूल कठुआ ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अपने अलंकरण समारोह का गौरवपूर्वक आयोजन किया। यह एक महत्वपूर्ण आयोजन था जो प्रधानाचार्य चारु अंजोत्रा के नेतृत्व में समर्पण और उत्कृष्टता की खोज को सम्मानित करने के लिए समर्पित था। समारोह को एक प्रतिष्ठित भारतीय सेना अधिकारी की उपस्थिति ने और भी गौरवान्वित किया। एक ऐसे अधिकारी जिनका गौरवशाली करियर, वीरता, रणनीतिक प्रतिभा और अनुकरणीय राष्ट्रीय सेवा से चिह्नित है, सभी उपस्थित लोगों के लिए प्रेरणा का एक गहन स्रोत रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत गहरी श्रद्धा के साथ हुई, जिसमें पारंपरिक दीप प्रज्वलन और ज्ञान एवं मार्गदर्शन के लिए आशीर्वाद हेतु एक मधुर सरस्वती वंदना का पाठ किया गया। स्कूल ने इंडियन पब्लिक स्कूल कठुआ की प्रधानाचार्या बलविंदर कौर का भी हार्दिक स्वागत किया, जिन्होंने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गंभीर गरिमा के क्षण में नवनियुक्त विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने नेतृत्व की शपथ लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया, तथा सार्वजनिक रूप से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ स्कूल समुदाय की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता की शपथ ली।दिन का मुख्य आकर्षण भारतीय सेना अधिकारी द्वारा दिया गया प्रेरक संबोधन था। उन्होंने छात्रों से अपने उद्देश्य की पहचान करने के लिए आत्म-खोज की यात्रा पर निकलने का जोरदार आग्रह किया और उन्हें अपने भाग्य का स्वामी बनने और जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों का अटूट साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह का समापन स्कूल के शिक्षा, खेल और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों के सम्मान और उनकी कड़ी मेहनत और सफलता का जश्न मनाने के साथ हुआ।

डीसी ने वित्तीय समावेशन और बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

कठुआ, 01 नवंबर (हि.स.)। विभिन्न वित्तीय समावेशन और बैंकिंग योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा के लिए कठुआ के उपायुक्त राजेश शर्मा ने विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई।

बैठक में सहायक मुख्य आयुक्त, मुख्य पुलिस अधिकारी, प्रमुख जिला प्रबंधक और विभिन्न बैंकों तथा संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और नागरिकों के बीच वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य संबंधित पहलों सहित प्रमुख वित्तीय योजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रगति का आकलन करते हुए उपायुक्त ने कुछ बैंकिंग संस्थानों के धीमे और खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लिया और उन्हें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में विशेष शिविर आयोजित करें ताकि विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कवरेज बढ़ाया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचे।

मेगा मल्टीस्पेशलिटी कैंपों में 156 मोतियाबिंद ऑपरेशन सहित 322 सर्जरी की गईं

कठुआ, 01 नवंबर (हि.स.)। स्वास्थ्य सेवा सुलभता और पहुँच को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक कठुआ जिले में मेगा मल्टीस्पेशलिटी सर्जरी कैंपों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की गई जिससे उन्नत चिकित्सा सेवाएँ लोगों के और करीब पहुँचीं।

यह पहल जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व और जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। डॉ. दुष्यंत चैधरी के नेतृत्व में रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से शिविरों की यह श्रृंखला आयोजित की गई, जो समुदाय को स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करने में प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के बीच एक मजबूत साझेदारी को दर्शाती है। शिविरों का आयोजन कठुआ के उपायुक्त राजेश शर्मा, स्वास्थ्य सेवाएं जम्मू के निदेशक डॉ. अब्दुल हामिद जरगर, जीएमसी कठुआ के प्रिंसिपल डॉ. सुरिंदर अत्री और कठुआ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय रैना की देखरेख में किया गया, जिसमें चिकित्सा पेशेवरों और सहायक कर्मचारियों के बीच प्रभावी समन्वय और टीम वर्क के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की गईं।राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कठुआ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसोहली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी में आयोजित इन मेगा कैंपों में नेत्र रोग, स्त्री रोग, हड्डी रोग और सामान्य शल्य चिकित्सा में विशेष शल्य चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की गईं, जिनका लाभ जिले के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों रोगियों को मिला पाँच दिनों के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने 156 मोतियाबिंद ऑपरेशन सहित 322 सर्जरी कीं, जिससे रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ और विशेष चिकित्सा हस्तक्षेपों तक समय पर पहुँच सुनिश्चित हुई।

क्राइम ब्रांच कश्मीर ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में ठगे गए 44,000 रुपये बरामद किए

श्रीनगर, 1 नवंबर (हि.स.)। ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ एक त्वरित कार्रवाई में क्राइम ब्रांच कश्मीर के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने दो अलग-अलग साइबर धोखाधड़ी के मामलों में कुल ठगे गए 44,000 रुपये सफलतापूर्वक वसूल किए और पीड़ितों के खातों में पैसे वापस कर दिए। अधिकारियों ने जनता से ऑनलाइन घोटालों के प्रति सतर्क रहने और हेल्पलाइन के माध्यम से साइबर अपराध की सूचना देने का आग्रह किया है। जारी एक बयान के अनुसार साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस क्राइम ब्रांच कश्मीर साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अपने निरंतर प्रयासों में आज दो साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों के ठगे गए पैसे बचाने में सफल रहा है।इसमें कहा गया है कि दो अलग-अलग ऑनलाइन शिकायतों में शामिल 24,446 रुपये और 20,000 रुपये की राशि क्रमशः पीड़ितों के बैंक खातों में वापस जमा कर दी गई है। सीआईसीई आम जनता से साइबर अपराधियों के झांसे में न आने और साइबर धोखेबाजों द्वारा की जा रही नवीनतम धोखाधड़ी के रुझानों से सावधान रहने की अपील करता है।

भूमि विवाद सुलझने के बाद केवाल का सरकारी स्कूल फिर से शुरू

जम्मू,, 1 नवंबर (हि.स.)। कई वर्षों से बंद पड़ा सरकारी प्राथमिक विद्यालय केवाल का भवन अब फिर से शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2000 में भूमि विवाद के कारण स्कूल भवन को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद स्कूल किराए के भवन में सीमित स्थान में चल रहा था। जिला विकास आयुक्त अभिषेक शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी मोहम्मद हफीज़ को स्थल पर जाकर विवाद को प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश दिए। निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीईओ ने संबंधित पक्षों से बातचीत कर विवाद का समाधान विवाद सुलझने के बाद विद्यार्थियों को फिर से मूल स्कूल भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें तीन कमरे पूरी तरह क्रियाशील बनाए गए हैं। स्कूल के पुनः खुलने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, और उन्होंने जिला प्रशासन का आभार जताया कि वर्षों बाद अब उनके बच्चों को घर के पास ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर फिर से मिला है।

जहरीला पदार्थ खाने से एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

शोपियां, 1 नवंबर (हि.स.)। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के पहनू इलाके में जहरीला पदार्थ खाने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों की पहचान रियासी निवासी लियाकत अहमद (18 वर्षीय) पुत्र मोहम्मद शाया खटाना और राजौरी निवासी इश्फाक अहमद खटाना (20 वर्षीय) पुत्र मोहम्मद जमील खटाना के रूप में हुई है जो उसी इलाके में रहते हैं। जानकारी के अनुसार दोनों ने दो दिन पहले अपने टेंट के अंदर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। उन्हें इलाज के लिए शोपियां जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ से बाद में उन्हें विशेष देखभाल के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल रेफर कर दिया गया।

हाईवे मेंटेनेंस कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करने वाला व्यक्ति रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया मृत

श्रीनगर, 1 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के सनत नगर इलाके में एक हाईवे मेंटेनेंस कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करने वाला 44 वर्षीय व्यक्ति रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया मृतक की पहचान उधमपुर के लाठी निवासी राज कुमार के रूप में हुई है जो हाईवे मेंटेनेंस का काम करने वाली एलएन मालवीय कंपनी में कार्यरत था। वह अस्थायी रूप से सनत नगर की हाउसिंग कॉलोनी में रह रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार राज कुमार ने सनत नगर में शराब पी थी और उसके बाद अपने कमरे में बेहोश हो गया। बाद में उसे अहमदिया अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया घटना के बाद शव को चिकित्सकीय-कानूनी औपचारिकताओं के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।

कठुआ में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता पद यात्रा का आयोजन

कठुआ, 01 नवंबर (हि.स.)। भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कठुआ जिला प्रशासन ने एकता पद यात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरदार पटेल द्वारा समर्थित एकता, अखंडता और देशभक्ति के आदर्शों का जश्न मनाया।

कार्यक्रम की शुरुआत कठुआ स्थित राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में पारंपरिक दीप प्रज्वलन और उसके बाद भारत माता और सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। प्रतिभागियों ने रियासतों को एकीकृत कर अखंड भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला ने राष्ट्र की विविध किन्तु

एकीकृत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया और एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संदेश को प्रतिबिम्बित किया। एकता पद यात्रा को कठुआ के डीडीसी अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) महान सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कठुआ के उपायुक्त राजेश शर्मा, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, कॉलेज के शिक्षक, छात्र और आम जनता शामिल हुई। रैली कठुआ शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए एकता और देशभक्ति का संदेश फैलाते हुए कठुआ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज के सभागार में समाप्त हुई।

स्थायी चुंबक मशीनों के डिज़ाइन में प्रभावी अनुकूलन एल्गोरिदम पर एक दिवसीय वेबिनार

कटरा , 1 नवंबर (हि.स.)। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा में स्थायी चुंबक मशीनों के डिज़ाइन में प्रभावी अनुकूलन एल्गोरिदम पर एक दिवसीय वेबिनार आयोजित किया गया। यह वेबिनार एसएमवीडीयू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूल द्वारा आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुसंधान प्रथाओं में सुधार लाना था। कार्यक्रम की शुरुआत एसओईई के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. तिरुमलसेट्टी चिरंजीवी के उद्घाटन भाषण से हुई जिन्होंने छात्रों और संकाय सदस्यों दोनों के दृष्टिकोण से कार्यशाला के महत्व को रेखांकित किया। इसके बाद एसओईई के सहायक प्रोफेसर डॉ. अंकिरेड्डी नरेंद्र ने पॉज़्नान यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी, पोलैंड के सहायक प्रोफेसर, विशेषज्ञ डॉ. लुकाज़ कनीपिंस्की का परिचय कराया। कार्यक्रम में प्रोफ़ेसर भोला झा, डॉ. कमल दीप, डॉ. प्रभु ओमर, आकाश दीप, शुभम चिप और डॉ. विक्रम कुमार सहित के सभी छात्रों, शिक्षण और गैर-शिक्षण सदस्यों की उत्साही भागीदारी देखी गई। प्रोफ़ेसर कुमुद रंजन झा, डीन फैकल्टी ऑफ़ इंजीनियरिंग और एचओडी ने वेबिनार के आयोजन के लिए अपना समर्थन दिया।

डॉ. लुकाज़ कनीपिंस्की की प्रस्तुति विद्युत चुम्बकीय उपकरणों के इष्टतम डिज़ाइन में मेटाहेयुरिस्टिक ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम के अनुप्रयोग की पड़ताल करती है। जेनेटिक एल्गोरिदम, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइज़ेशन, बैट एल्गोरिदम, ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइज़ेशन और कोयल सर्च जैसे एल्गोरिदम जटिल विवश अनुकूलन समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी साबित हुए हैं, खासकर जब परिमित तत्व विधि मॉडल से निपटते हैं वेबिनार का समापन एसओईई के सहायक प्रोफेसर डॉ. जतिनकुमार सोनी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

उपराज्यपाल सचिवालय में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया

लेह, 1 नवंबर। उपराज्यपाल सचिवालय में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस को याद किया गया। भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत, भारत भर के राज निवासों और राजभवनों में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का सम्मान करना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और क्षेत्रों के बीच एकता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और परंपराओं की समझ और प्रशंसा को गहरा करना और देश के विविध क्षेत्रों के बीच एकजुटता की भावना को सुदृढ़ करना था।पंजाब की मूल निवासी, प्रशासनिक सचिव भानु प्रभा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय समृद्धि तभी संभव है जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ मिलकर फलें-फूलें। उन्होंने भारत की प्रगति में नागरिकों की ज़िम्मेदारी पर प्रकाश डाला और पंजाब की उपजाऊ भूमि की विरासत और देश के स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान का उल्लेख किया, जहाँ से कई प्रतिष्ठित नेता और स्वतंत्रता सेनानी उभरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रशासनिक सचिव भूपेश चौधरी ने भारत की विविधता में निहित शक्ति के बारे में बात की—जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, समुदाय और धर्म समाहित हैं।

मंत्री डार ने चंसर फिश फार्म में डेनमार्क ब्राउन ट्राउट बीज स्टॉकिंग की शुरुआत की

जम्मू,, 1 नवंबर (हि.स.। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, सहकारिता एवं चुनाव विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने आज कुलगाम के चंसर फिश फार्म का दौरा कर डेनमार्क से आयातित ब्राउन ट्राउट मछली के बीज के स्टॉकिंग की शुरुआत की। मंत्री ने बताया कि यह जम्मू-कश्मीर की पहली हैचरी है, जहां डेनमार्क नस्ल की ब्राउन ट्राउट मछली को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

जावेद अहमद डार ने कहा कि सरकार मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग बागवानी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए नए फल मंडियों की स्थापना कर रहा है, जिससे केंद्रशासित प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कश्मीर विश्वविद्यालय में डॉ. राही मासूम रज़ा की विरासत पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन

श्रीनगर, 01 नवंबर (हि.स.)। कश्मीर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को डॉ. राही मासूम रज़ा की विरासत पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। संगोष्ठी में भारत और विदेश के 40 से ज्यादा विद्वान, जिनमें क़तर, अमेरिका और प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हैं, रज़ा के साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान पर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे।उपराज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि डॉ. राही मासूम रज़ा नई पीढ़ियों को सपने देखने और अपनी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सिन्हा ने कहा कि इस प्रसिद्ध लेखक का सबसे बड़ा उपहार आत्म-साक्षात्कार का संदेश और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कला है। उन्होंने आग्रह किया कि रज़ा के आदर्शों को अकादमिक मंचों से आगे बढ़ाया जाए और जनता के साथ व्यापक रूप से साझा किया जाए।

जी.जी.एच.एस.एस. भद्रवाह में नवमी कक्षा के परिणाम घोषित - अव्वल विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

आमिर इक़बाल ख़ान

भद्रवाह, 1 नवम्बर। सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (GGHSS) भद्रवाह में शनिवार को नवमी कक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के साथ ही पूरे विद्यालय परिसर में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया। प्रधानाचार्य शिफायत अली ने विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह मेहनत और लगन से कार्य करने का संदेश दिया।

विद्यालय परिसर में आयोजित घोषणा समारोह में छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों की बड़ी संख्या उपस्थित रही। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अली ने कहा, हमारी छात्राओं ने अपनी मेहनत और समर्पण से विद्यालय का नाम रोशन किया है। मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। उनके संबोधन पर उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया।

प्रधानाचार्य ने शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि हमारे अध्यापकों ने विद्यार्थियों को तर्कशील सोच और आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है। उनकी मेहनत और समर्पण ही इस सफलता की असली नींव है।

समारोह के दौरान अव्वल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया, जिससे उनके साथियों में भी उत्साह का संचार हुआ। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य शिफायत अली ने छात्राओं से आगे भी ऊँचाइयों को छूने का आह्वान करते हुए कहा, सफलता की कोई सीमा नहीं होती, मेहनत और दृढ़ निश्चय से हर मंज़िल पाई जा सकती है।

विद्यालय प्रशासन ने सभी सफल विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हुए उनसे आग्रह किया कि वे त्न्न।।स्स भद्रवाह की उत्कृष्टता की परंपरा को आगे बढ़ाएँ और शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसालें कायम करें।

पुलिस ने लापता लड़की को खोजकर उसके परिवार से मिलवाया

कठुआ, 01 नवंबर (हि.स.)। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के समग्र पर्यवेक्षण में कठुआ पुलिस ने पुलिस पोस्ट नगरी के अधिकार क्षेत्र में एक लापता लड़की का पता लगाया और उसे उसके परिवार के सदस्यों से मिलाया।

जानकारी के अनुसार 26-10-2025 को पुलिस पोस्ट नगरी में कोमल देवी पुत्री सुरिंदर कुमार निवासी पडयारी तहसील जिला कठुआ की गुमशुदगी की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस चैकी कठुआ में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और पुलिस पोस्ट नगरी के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय कठुआ रविंदर सिंह और थाना प्रभारी कठुआ संदीप चिब के पर्यवेक्षण में एक टीम ने विभिन्न स्थानों पर खोजबीन की, तकनीकी सहायता और समय पर मानवीय हस्तक्षेप की मदद से लापता लड़की को बरामद किया। सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद उक्त लापता लड़की को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया।

उप-मंडल प्रशासन हीरानगर द्वारा पदयात्रा आयोजित

कठुआ, 01 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में उप-मंडल प्रशासन हीरानगर द्वारा एसडीएम हीरानगर फुलैल सिंह की देखरेख में हीरानगर में पदयात्रा का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर विधायक हीरानगर एडवोकेट विजय शर्मा मुख्य अतिथि थे।

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय रंग-बिरंगी रंगोली और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विधायक हीरानगर और एसडीएम हीरानगर ने जनता और युवाओं को भारत की एकता और अखंडता को आकार देने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए एकता की शपथ भी दिलाई गई।

कार्यक्रम में बीडीओ हीरानगर, एक्सईएन आरएंडबी हीरानगर, ईओ एमसी हीरानगर, बीएमओ हीरानगर, एसडीईओ हीरानगर, जल शक्तिध्जेपीडीसीएल के एईएस, एसएचओ हीरानगर, शिक्षा विभाग के अधिकारी/शिक्षक, गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न स्कूलों, आईटीआई, डिग्री कॉलेज के छात्र-छात्राएँ सहित उप-मंडल प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

संपादकीय

अनियमित रोज़गार की विरासत

जम्मू-कश्मीर सरकार लगभग 97,000 अस्थायी और आकस्मिक कर्मचारियों के नियमितीकरण की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की ओर अग्रसर है, और उसे एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो आधुनिक जम्मू-कश्मीर की राजनीति जितनी ही पुरानी है—एक ऐसी समस्या जो काफी हद तक उसकी अपनी ही बनाई हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), जो आज प्रशासन का नेतृत्व कर रही है, को अब उस व्यवस्था के परिणामों का सामना करना होगा जो तीन दशक से भी पहले उसके शासन में पनपी थी। दिहाड़ी और आकस्मिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रथा 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई, जब राजनीतिक नेताओं ने—सभी क्षेत्रों में, लेकिन सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकारों के तहत—वफ़ादारी को पुरस्कृत करने या स्थानीय माँगों को पूरा करने के लिए अस्थायी नियुक्तियों का सहारा लिया। जो एक अस्थायी उपाय के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही संस्थागत संरक्षण में बदल गया। कई लोगों की अनौपचारिक रूप से भर्ती की गई, अक्सर भविष्य में नियमितीकरण के वादे के साथ—ऐसे वादे जिन्हें बाद की सरकारों ने दोहराया लेकिन शायद ही कभी पूरा किया।

1994 में, डॉ. फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान, सरकार ने एसआरओ-64 जारी किया, जिसका औपचारिक नाम जम्मू-कश्मीर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी (नियमितीकरण) नियम, 1994 था। हालाँकि इसे राज्यपाल शासन के दौरान लागू किया गया था, लेकिन बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे अपनाया और लागू किया। इस नीति का उद्देश्य अनियमित नियुक्तियों की अव्यवस्थित व्यवस्था में व्यवस्था लाना था। इसके बजाय, इसने एक समानांतर कार्यबल संरचना को वैधता प्रदान की जो राजनीतिक कृपालुता के माध्यम से लगातार विस्तारित होती रही। प्रत्येक आगामी प्रशासन - जिसमें बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सरकारें भी शामिल थीं - आधिकारिक प्रतिबंधों के बावजूद नई नियुक्तियाँ करता रहा।

आज, 97,000 से ज़्यादा कर्मचारी अनिश्चितता में हैं - आधार-आधारित प्रोफ़ाइलिंग के माध्यम से पंजीकृत हैं, लेकिन अभी भी अपने भविष्य पर स्पष्टता का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके नियमितीकरण के मानवीय, कानूनी और वित्तीय पहलुओं की जाँच के लिए गठित मार्च 2025 समिति, इस दशकों पुरानी गड़बड़ी को दूर करने का नवीनतम प्रयास है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वर्तमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार अंततः इस अनियमितता की जड़ों तक पहुँच पाएगी, या केवल देरी और तुष्टिकरण का चक्र जारी रखेगी?

जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। 1990 के दशक में इस व्यवस्था के जन्म की अध्यक्षता करने वाली और अब दोबारा सत्ता में आने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति से कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदार है—उनके प्रति समाधान की भी। सरकार को एक पारदर्शी, चरणबद्ध और वित्तीय रूप से व्यवहार्य नियमितीकरण योजना लागू करके राजनीतिक साहस का परिचय देना चाहिए जो तदर्थवाद को स्थायी रूप से समाप्त करे। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य की भर्तियाँ योग्यता और मंजूरी के अनुसार हों, और राजनीतिक संरक्षण के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएँ।

दशकों से, ये कर्मचारी बिना किसी गरिमापूर्ण नौकरी की सुरक्षा के आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के पास अब अपनी विरासत को सुधारने का दुर्लभ अवसर है। अगर वह इसमें सफल होती है, तो यह प्रशासनिक जिम्मेदारी के एक नए युग की शुरुआत होगी। अगर वह असफल होती है, तो यह साबित होगा कि जम्मू-कश्मीर में इतिहास खुद को दोहराता रहता है।

जनस्वास्थ्य बनाम मुनाफ़ा- भ्रामक औषधि प्रचार का बढ़ता जाल

सीमापार डिजिटल मीडिया ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। अधिकांश बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भारत में कार्य करती हैं, परंतु उनका मुख्यालय विदेश में है। भारत में दिखने वाले विज्ञापनों का संचालन विदेश से होता है। जब कोई नियामक संस्था कार्रवाई करना चाहती है, तब क्षेत्राधिकार की दीवारें आ खड़ी होती हैं। भारत में इन कंपनियों की सहायक इकाइयाँ कहती हैं कि वे केवल विपणन एजेंट हैं, नीति निर्धारण में उनकी कोई भूमिका नहीं। इससे कानूनी जवाबदेही लगभग असंभव हो जाती है।

- डॉ सत्यवान सौरभ

भारतीय समाज में स्वास्थ्य केवल व्यक्ति के अस्तित्व का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का भी प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित 'जीवन के अधिकार' में स्वास्थ्य का अधिकार निहित है। किंतु जब औषधियों के नाम पर फैलाए जाने वाले झूठे विज्ञापन जनमानस को भ्रमित करते हैं, तब यह अधिकार संकट में पड़ जाता है।

सन् 1954 में पारित औषधि तथा चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम अर्थात् (डीएमआरए) का उद्देश्य ऐसे विज्ञापनों पर नियंत्रण था जो गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, मधुमेह, बांझपन अथवा मानसिक रोगों के उपचार का झूठा दावा करते हैं। परंतु इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के आगमन ने इस कानून की शक्ति को लगभग निष्प्रभावी बना दिया है।

आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल जैसे मंचों पर आयुर्वेद से कैंसर का इलाज, 30 दिन में डायबिटीज खत्म, अथवा डॉक्टर X की हर्बल दवा से चमत्कारी उपचार जैसे संदेशों की भरमार है। इन विज्ञापनों के पीछे कोई चिकित्सकीय प्रमाण नहीं होता, फिर भी लाखों लोग इन्हें देखकर प्रभावित होते हैं। यह स्थिति केवल कानूनी चुनौती नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक संकट भी है।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपने एल्गोरिद्म के माध्यम से वही सामग्री बढ़ावा देते हैं जो अधिक क्लिक अथवा लोकप्रियता लाती है। अर्थात् जो जितना सनसनीखेज़ अथवा चमत्कारी दिखता है, वही शीर्ष पर पहुँचता है। परिणामस्वरूप झूठे चिकित्सीय दावे और तीव्रता से फैलते हैं। कंपनियाँ इस प्रक्रिया से भारी आय अर्जित करती हैं, परंतु जिम्मेदारी से बचने हेतु स्वयं को मात्र मध्यस्थ घोषित करती हैं।

'मध्यस्थ प्रतिरक्षा' की अवधारणा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दी गई थी ताकि सोशल मीडिया अथवा खोज इंजन पर डाली गई सामग्री के लिए उन्हें दायित्व से मुक्त रखा जा सके। परंतु अब यही प्रावधान उन प्लेटफ़ॉर्मों के लिए सुरक्षा कवच बन गया है जो सीधे विज्ञापन प्रसारित करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं। जब कोई विज्ञापन प्रायोजित अथवा भुगतान किया गया होता है, तब प्लेटफ़ॉर्म को मात्र मध्यस्थ नहीं माना जा सकता।

भारत में डीएमआरए की प्रवर्तन प्रणाली अत्यंत कमजोर है। इस अधिनियम के तहत दंड के प्रावधान हैं, परंतु न तो कोई विशेष निगरानी संस्था है और न ही डिजिटल विज्ञापनों की जाँच के लिए तकनीकी तंत्र।

फलस्वरूप, उल्लंघनकर्ता आसानी से बच निकलते हैं। अनेक बार जब कोई शिकायत दर्ज होती है, तब तक वह विज्ञापन हटाकर नया अभियान आरंभ कर दिया जाता है।

इसके विपरीत अमेरिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डिजिटल स्वास्थ्य विज्ञापनों पर कठोर नियंत्रण है। वहाँ कंपनियों को हर विज्ञापन की सत्यता का प्रमाण देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) बिना अनुमति वाले चिकित्सीय दावों पर त्वरित कार्रवाई करता है। वहीं भारत में वही कंपनियाँ गौमूत्र से कैंसर ठीक अथवा एक कैप्सूल में सौ रोगों का अंत जैसे विज्ञापन निःसंकोच प्रसारित करती हैं। यह दोहरा नियामक दृष्टिकोण भारतीय उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।

सीमापार डिजिटल मीडिया ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। अधिकांश बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भारत में कार्य करती हैं, परंतु उनका मुख्यालय विदेश में है। भारत में दिखने वाले विज्ञापनों का संचालन विदेश से होता है। जब कोई नियामक संस्था कार्रवाई करना चाहती है, तब क्षेत्राधिकार की दीवारें आ खड़ी होती हैं। भारत में इन कंपनियों की सहायक इकाइयाँ कहती हैं कि वे केवल विपणन एजेंट हैं, नीति निर्धारण में उनकी कोई भूमिका नहीं। इससे कानूनी जवाबदेही लगभग असंभव हो जाती है।

एल्गोरिद्मिक लक्ष्य निर्धारण भी एक बड़ी समस्या है। विज्ञापन अब स्थिर नहीं रहते — वे उपयोगकर्ता की रुचि, खोज इतिहास और स्थान के आधार पर बदलते रहते हैं। इससे निगरानी, साक्ष्य एकत्रण तथा दंड प्रक्रिया और कठिन हो जाती है। कोई वीडियो अथवा पोस्ट कुछ ही घंटों में गायब हो सकता है, जिससे अपराध सिद्ध करना कठिन हो जाता है।

भारत में कुछ सकारात्मक प्रयास अवश्य हुए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 2022 में भ्रामक विज्ञापनों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं प्रभावशाली प्रचारकों को भी उत्तरदायी ठहराया है। आयुष मंत्रालय ने भी डीएमआरए के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की माँग की है। किंतु यह सभी कदम अभी भी सीमित और प्रतिक्रियात्मक हैं। यदि भारत को जनता के स्वास्थ्य अधिकार की रक्षा करनी है, तो डिजिटल विज्ञापन नियंत्रण को दृढ़ता से लागू करना होगा। इसके लिए कुछ आवश्यक सुधार निम्नलिखित हैं:

-पहला, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों को मात्र मध्यस्थ नहीं, बल्कि प्रकाशक के रूप में परिभाषित किया जाए ताकि वे प्रसारित विज्ञापनों की सामग्री के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हों।

-दूसरा, डीएमआरए उल्लंघन को 'गंभीर अपराध' की श्रेणी में लाया जाए और इसके तहत कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएँ।

-तीसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वचालित निगरानी तंत्र विकसित किया जाए जो प्रतिबंधित दावों वाले शब्दों अथवा चित्रों को स्वतः पहचानकर रोक सके।

-चौथा, सीमापार दायित्व सुनिश्चित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा बनाया जाए ताकि भारत में प्रसारित विज्ञापनों के लिए विदेशी कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सके।

-पाँचवाँ, जन-जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जब तक नागरिक स्वयं झूठे विज्ञापनों की पहचान नहीं करेंगे, तब तक कोई कानून प्रभावी नहीं हो सकता।

डिजिटल युग में औषधि विज्ञापन केवल व्यापार नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य का प्रश्न है। भारत को प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि दायित्व-आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा। बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लाभ से ऊपर जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना ही संविधान प्रदत्त 'स्वास्थ्य के अधिकार' की सच्ची रक्षा होगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

डीप फेक का बढ़ता खतरा

लालजी जायसवाल

डीपफेक या मिलावटी ऑडियो-वीडियो से किसी व्यक्ति के सामाजिक या व्यक्तिगत नुकसान को रोकने के लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है। जल्द ही ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डाले जाने वाले मिलावटी कंटेंट पर एक लेबल लगाना अनिवार्य होगा। ताकि यूजर्स को यह पता लग जाए कि जो वीडियो या ऑडियो वह देख या सुन रहा है, वह असली नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने इस संबंध में मसौदा जारी किया है, जिस पर स्टेकहोल्डर्स से प्रतिक्रिया मांगी गई है। प्रतिक्रिया देने का काम अगले पंद्रह दिनों में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इस नियम को लागू किया जा सकता है।

मंत्रालय के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मिलावटी कंटेंट का पता लगाने की जिम्मेदारी इंटरमीडिएरिज की होगी। बता दें कि इंटरमीडियरिज किसी ऐसे टूल का इस्तेमाल करेंगे जो कंटेंट को प्लेटफार्म पर पोस्ट करते ही यह पता लगा लेगा कि कंटेंट में मिलावट है और फिर उस पर लेबल लगा दिया जाएगा। फिलहाल सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें मीडिया में बनी रहती हैं कि डीप फेक वीडियो के जरिये किसी नामचीन हस्ती के चरित्र हनन की कोशिश की गई या एआई की मदद से किसी की आवाज की नकल करके आर्थिक मुनाफा कमा लिया गया। हाल ही में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गूगल और यू-ट्यूब के खिलाफ चार करोड़ रुपये के हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। इस दंपति को खुद से जुड़े काल्पनिक एआई कंटेंट वाले वीडियो यू-ट्यूब और गूगल पर प्रसारित किए जाने के खिलाफ अदालत से संरक्षण की मांग करनी पड़ी।

निःस्संदेह, सोशल मीडिया पर जिस तरह की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों की भरमार देखने को मिलती है, वह अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे का सीधा-सीधा अतिक्रमण दिखती है। इसलिए इसका नियमन वक्त की मांग है। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान भी किसी प्रत्याशी की छवि को खराब करने के लिए डीपफेक वीडियो-आडियो का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ अब किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से कंटेंट को हटाने का निर्देश संयुक्त सचिव या डीआईजी रैंक के अधिकारी ही दे सकेंगे। ध्यातव्य है कि आगामी एक नवंबर से यह नियम लागू हो जाएगा। विभिन्न राज्यों में अभी दरोगा स्तर के अधिकारी ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म से कंटेंट हटाने का फरमान जारी कर रहे थे। राज्य सरकार की तरफ से इस नियम में बदलाव की मांग की जा रही थी। संयुक्त सचिव और डीआइजी पुलिस स्तर के अधिकारी की तरफ से अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कंटेंट हटाने का निर्देश जाता है और कंटेंट को नहीं हटाया जाता है तो उस प्लेटफार्म को भी कंटेंट डालने वाले के बराबर जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस प्रकार की कार्रवाई की समीक्षा मासिक स्तर पर सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। इस नए नियम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि किस स्तर के अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कंटेंट हटाने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अब आने वाले समय में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग रोकने में मदद मिल सकेगी।

सोशल मीडिया मंचों के नकारात्मक उदाहरणों का हवाला देकर हम इसके अच्छे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मंच स्वतंत्र अभिव्यक्ति के सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। इन मंचों की मदद से आम लोग न सिर्फ अपनी बात शासन- प्रशासन तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, बल्कि कई बार इनके दबाव में अपराधियों को दबोचने में भी प्रशासन को मदद मिली है। निर्विवाद तथ्य यह भी है कि लाखों लोग इनकी मदद से अपनी रचनाशीलता को नई धार दे रहे हैं और ये उनकी आमदनी का जरिया बन रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस बार काफी सतर्कता बरतते हुए प्रावधान प्रस्तावित किए हैं।

मौजूदा प्रस्तावों में सरकार ने काफी सावधानी बरतते हुए पचास लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाले सोशल मीडिया मंचों से यह अपेक्षा की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपलोड सामग्री कृत्रिम नहीं हैं। ऐसी किसी भी सामग्री को उन्हें प्रमुखता से चिह्नित करना होगा। वाकई यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे डिजिटल दुनिया की अराजकता को नियंत्रित करना आसान होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने में भी आसानी होगी। सरकार ने गलत कंटेंट हटाने वाले डिजिटल मंचों को वैधानिक संरक्षण देने की बात भी कही है और छ नवंबर तक इन मसौदों पर लोगों की राय मांगी है तो यह अवसर है उन लोगों के लिए जिन्हें इन नियमों को लेकर कोई अंदेशा है। उन्हें अपने अंदेशे और आपत्तियां अवश्य दर्ज करानी चाहिए, ताकि पारदर्शी व प्रभावी नियम वजूद में आ सकें।

तकनीकी युग में जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन को आसान बना रही है, वहीं इसका एक भयावह रूप डीप फेक समाज के लिए गंभीर संकट बनता जा रहा है। गौरतलब है कि डीपफेक आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक प्रभावशाली तकनीक है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज और हावभाव को इस प्रकार बदला या पुनःनिर्मित किया जा सकता है कि असली और नकली में अंतर करना लगभग असंभव हो जाता है। डीप फेक तकनीक से ऐसे वीडियो, ऑडियो या फोटो तैयार किए जा सकते हैं जो पूरी तरह झूठे होते हैं, पर देखने या सुनने में एकदम असली लगते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश में जहाँ सोशल मीडिया सूचना का प्रमुख माध्यम बन चुका है, वहाँ इस तकनीक का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कभी राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने, कभी सांप्रदायिक तनाव फैलाने, तो कभी मशहूर व्यक्तियों की छवि धूमिल करने में। समस्या यह है कि आम नागरिक अक्सर डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण झूठे कंटेंट को सच मान बैठते हैं, और यही डीप फेक की सबसे खतरनाक परिणति है।

समाज में जन-जागरूकता ही इसका सबसे प्रभावी हथियार बन सकती है। स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक, और गाँवों से लेकर शहरों तक, डिजिटल शिक्षा और मीडिया साक्षरता को अभियान के रूप में फैलाना होगा। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों को भी ऐसे पहचान तंत्र विकसित करने होंगे जो डीप फेक कंटेंट को तुरंत चिन्हित कर सकें। साथ ही नागरिकों को यह समझना होगा कि हर वायरल वीडियो सच नहीं होता। जबतक समाज सूचना को परखने की आदत नहीं डालेगा, तबतक डीप फेक लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता रहेगा। जागरूक नागरिक ही इस डिजिटल युग के असली प्रहरी बन सकते हैं, जो तकनीक को साधन बनाएँ, हथियार नहीं।

डीप फेक जैसी तकनीकी चुनौती का निदान केवल कानून बनाकर संभव नहीं, बल्कि इसके लिए तकनीकी, शैक्षिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। सबसे पहले, सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और डिजिटल इंडिया कानूनों में संशोधन कर डीप फेक सामग्री बनाने और प्रसारित करने वालों पर कड़ी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। साथ ही, देश में ऐसे स्वदेशी एआई आधारित पहचान तंत्र विकसित किए जाने चाहिए जो डीप फेक वीडियो या ऑडियो को तुरंत पहचान सकें। स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल साक्षरता और मीडिया नैतिकता को शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा ताकि नई पीढ़ी तकनीक का उपयोग समझदारी से करे। नागरिक समाज, मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया कंपनियों को मिलकर फैक्ट-चेकिंग नेटवर्क को सशक्त बनाना चाहिए ताकि झूठी सूचनाओं का प्रसार रोका जा सके। डीप फेक की रोकथाम तभी संभव है जब स्वयं भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच करने की आदत डालें। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तकनीक तभी कल्याणकारी बन सकती है, जब उसका उपयोग विवेक और जिम्मेदारी के साथ किया जाए।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

अमेरिका में एक भारतीय नारी का साहस

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

अमेरिका की धरती आज जिस रूप में एक वैश्विक अवसरों की भूमि के रूप में जानी जाती है, उसमें भारतीय मूल के लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। चाहे बात विज्ञान, तकनीकी नवाचार, शिक्षा, व्यवसाय या सांस्कृतिक विविधता की हो, भारतीय अमेरिकियों ने हर क्षेत्र में अपनी अद्वितीय छाप छोड़ी है।

हाल ही में मिसिसिपी विश्वविद्यालय में एक भारतीय मूल की महिला द्वारा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से आव्रजन नीतियों पर खुले मंच से सवाल पूछना इसी साहस और सामाजिक जागरूकता का उदाहरण है। इस घटना को सिर्फ एक बहस मत मानिए, यह तो उस प्रवासी समुदाय की आवाज थी जो अमेरिका की प्रगति में प्रत्यक्ष योगदान देने के बावजूद नीतिगत भेदभाव का सामना करता है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में 54 लाख (5.4 मिलियन) से अधिक भारतीय एवं भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। यह संख्या उन्हें अमेरिका में चीनी-अमेरिकियों के बाद दूसरा सबसे बड़ा एशियाई जातीय समूह बनाती है। यह समुदाय अमेरिका की कुल आबादी का लगभग 1.6% है। भारतीय अमेरिकी समुदाय उच्च शिक्षा और तकनीकी दक्षता में अग्रणी होने के साथ ही यहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है।

मैनहैटन इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, एक औसत भारतीय प्रवासी और उसका परिवार अगले 30 वर्षों में अमेरिकी संघीय खज़ाने को लगभग 1.7 मिलियन डॉलर की बचत प्रदान करता है यह सभी प्रमुख प्रवासी समूहों में सबसे ऊँचा आँकड़ा है। यानी चीन के लोग भले ही अमेरिका में अधिक हों, किंतु अमेरिका के खजाने को सबसे अधिक यदि कोई भरता है तो वे भारतीय हैं।

भारतीय अमेरिकी पेशेवर विशेष रूप से आईटी, चिकित्सा, वित्त, इंजीनियरिंग और उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी हैं। उदाहरण के लिए, एच-1बी वीजा कार्यक्रम में लगभग 73 प्रतिशत हिस्सेदारी भारतीयों की रही है, जो उच्च कौशल वाले तकनीकी पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करती है। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एडोबी के शांतनु नारायण और आईबीएम जैसी कंपनियों में शीर्ष नेतृत्व में भारतीय मूल के लोग इस बात का प्रमाण हैं कि भारतीय प्रतिभा ने अमेरिकी कॉर्पोरेट परिदृश्य को बदलकर रख दिया है। इसलिए ही बुद्धि कौशल के मामले में सबसे अधिक भारतीयों की डिमांड वहां रहती है।

यह भी एक तथ्य है, भारतीय अमेरिकियों का औसत वार्षिक पारिवारिक आय अमेरिका के औसत से लगभग 80 प्रतिशत अधिक है। वे अमेरिका की जनसंख्या का 1.5 प्रतिशत होते हुए भी संघीय कर राजस्व में 5 से 6 प्रतिशत योगदान देते हैं। उनके व्यवसायों और स्टार्टअप्स से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 11 से 12 मिलियन रोजगार अवसर जुड़े हैं। सिलिकॉन वैली में स्थापित हर चौथे स्टार्टअप की नींव किसी भारतीय या भारतीय मूल के उद्यमी ने रखी है। कहना होगा कि यह भारतवंशियों के नवाचार-केन्द्रित दृष्टिकोण का परिचायक है।

अब बात अमेरिका की आव्रजन नीति की। वस्?तुतः ये लंबे समय से राजनीतिक विवादों का विषय रही है। विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान कड़े प्रतिबंधों और America First" नीति के कारण कई वैध प्रवासी भी प्रभावित हुए हैं। इन नीति ने भारतीय समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ाई है, जबकि अधिकांश भारतीय प्रवासी पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया से अमेरिका पहुंचे हैं, फिर भी इमिग्रेशन सख्ती की लहर ने उन्हें भी अपने अस्तित्व के लिए सजग और संगठित होने पर मजबूर किया है।

इसी संदर्भ में मिसिसिपी विश्वविद्यालय की वह घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमें एक भारतीय मूल की महिला ने उपराष्ट्रपति वेंस से सार्वजनिक मंच पर सवाल किया; क्हम नियमों से आए हैं, मेहनत से जी रहे हैं, तो हमें बाहर क्यों किया जा रहा है?फ यह प्रश्न मात्र भावनात्मक नहीं है, यह अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्य, समानता और न्याय के सिद्धांतों को पुनः परिभाषित करने का आह्वान है। वेंस ने जब उत्तर दिया कि कम प्रवासी आने चाहिए ताकि देश का सामाजिक ढांचा बचा रहे, तो यह तर्क बहुसांस्कृतिक समाज की जटिलताओं को समझने में विफल रहा। क्?योंकि अमेरिका का इतिहास बताता है कि विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति रही है और भारतीय प्रवासियों ने इस विविधता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। यदि भारतीय अमेरिका नहीं जाते तो आज अमेरिका जिस विकसित रूप में दिखाई देता है, वह भी नहीं होता!

इसी तरह से कार्यक्रम के दौरान महिला द्वारा उपराष्ट्रपति के अंतरधार्मिक विवाह पर सवाल उठाना भी भारतीय प्रवासियों के सांस्कृतिक आत्मबोध को दर्शाता है। भारतीय समुदाय अपनी धार्मिक आस्था, पारिवारिक मूल्य और सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए भी अमेरिकी समाज में गहराई से रच-बस गया है। जैसा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की पत्नी उषा वेंस को हम देख सकते हैं, जो पूरी तरह से हिन्?दू धर्म का पालन करती हैं। इसी तरह से अनेक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो यहां सांस्कृतिक एकता और वैश्विक सौहार्द का संदेश मजबूत कर रहे हैं।

भारतीय अमेरिकियों ने व्यवसाय और तकनीकी जगत के साथ ही राजनीति और सामाजिक नेतृत्व में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। इस दृष्टिकोण से कई नाम देखे जा सकते हैं। कमला हैरिस, अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, श्री थानेदार, अरुणा मिलर, विवेक मूर्ति निक्की हेली बॉबी जिंदल, प्रीति भरगावा, सीमा वर्मा, काश्यप (कश) पटेल, विवेक रामास्वामी, सुहास सुब्रमण्यम, रिचर्ड आर. वर्मा, प्रीति बंसल, अंजली चतुर्वेदी, माला अडिगा, सेमी वर्मा, नील कशकारी और ऐसे ही अन्य नाम हैं। आज कई भारतीय अमेरिकी अब अमेरिकी कांग्रेस, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में निर्वाचित होकर नीति निर्माण की मुख्यधारा में हैं।

नई पीढ़ी के भारतीय अमेरिकी छात्र विश्वविद्यालयों में शिक्षा, शोध और नवाचार में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वे सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और तकनीकी नैतिकता जैसे विषयों पर अग्रिम सोच रखते हैं। यह प्रवृत्ति बताती है कि भारतीय समुदाय यहां सिर्फ आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं है, अमेरिकी लोकतंत्र की मूल चेतना का भी पूर्ण हिस्सा बन चुका है।

अतः वर्तमान संदर्भ में यदि कुछ शब्?दों में हम समझें तो भारतीयों का ज्ञान, साहस, बुद्धिमत्ता और श्रम, समृद्धि बल ही अमेरिका की सफलता की कहानी का अभिन्न अध्याय है। यहां रह रहे भारत वासियों ने अपने परिश्रम, शिक्षा और नैतिक आचरण से यह सिद्ध किया है कि किसी भी देश की प्रगति केवल नीतियों पर नहीं, बल्कि लोगों की लगन और समर्पण पर निर्भर करती है।

वस्तुत-आज आवश्यकता इस बात की है कि अमेरिकी इमिग्रेशन नीति भारतीय समुदाय के इस योगदान को पहचाने और उसके अनुरूप सम्मान व अवसर सुनिश्चित करे।

मिसिसिपी की ये घटना भारतीयों का साहस है। जो लोग अमेरिका की "America First" नीति के नाम पर भारतीयों पर जुल्म कर रहे हैं, वे समझ जाएं कि ऐसा करके वे अपने देश को ही कमजोर कर रहे हैं।

भारत ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए : नहीं चला ऋषभ पंत का बल्ला, भारत ने बनाए 234 रन

एजेंसी

बेंगलुरू : भारत ए टीम दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चार दिवसीय क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को 234 रन पर आउट हो गई जिसमे ऋषभ पंत 17 रन का ही योगदान दे सके। दक्षिण अफ्रीका ए ने कल के स्कोर नौ विकेट पर 299 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन पहले ही सत्र में 309 रन पर आउट हो गई। भारत ए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और आफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायेन ने 61 रन देकर पांच विकेट चटकाए जिससे दक्षिण अफ्रीका ए को 75 रन की बढत मिल गई। युवा आयुष म्हात्रे ही टिककर खेल सके जिन्होंने 76 गेंद में 65 रन जोड़े। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका ए ने बिना किसी नुकसान के 30 रन बना लिए थे और अब उसके पास 105 रन की बढ़त हो गई है। जोर्डन हरमान 12 और लेसेगो सेनोकवाने नौ रन बनाकर खेल रहे हैं। दूसरे दिन सभी की नजरें पंत पर लगी थी जो तीन महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौट रहे थे लेकिन विकेट के सामने वह टिक नहीं सके। उन्होंने छठी गेंद पर सुब्रायेन को मिडआन पर चौका लगाया। इसके बाद शेपो मोराकी को स्क्वेयर लेग पर चौका लगाकर क्रीज पर जमने के संकेत दिये । लेकिन जुबैर हमजा की गेंद को खेलें या नहीं खेलें की दुविधा में वह गली में कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। इससे पहले चोटिल एन जगदीशन की जगह खेल रहे साइ सुदर्शन 94 गेंद में 38 रन की पारी में कहीं सहज नहीं लगे।

अश्विन का फूटा गुस्सा, इस खिलाड़ी को टीम से बाहर रखने पर उठाए सवाल

मेलबन। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में मिचेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 4 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन इस मुकाबले के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है- अर्शदीप सिंह को आखिर क्यों बाहर रखा गया भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अर्शदीप जैसे गेंदबाज को लगातार बेंच पर बैठाना समझ से परे है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'अगर बुमराह टीम में हैं, तो उनके बाद आपके दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह का नाम सबसे पहले होना चाहिए। और अगर बुमराह नहीं खेल रहे, तो अर्शदीप को पहला विकल्प होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि अर्शदीप को बार-बार इस टीम से कैसे बाहर रखा जा रहा है।'

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे ने पुर्तगाल की अंडर 16 टीम के लिए किया डेब्यू

अंताल्या : सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बड़े बेटे ने पुर्तगाल की अंडर 16 टीम के लिए पदार्पण किया। क्रिस्टियानिन्हो के नाम से मशहूर 15 वर्ष के क्रिस्टियानो डोस सांतोस को तुर्की के खिलाफ फेडरेशंस कप टूर्नामेंट के मैच में 90वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर उतारा गया। पुर्तगाल ने यह मैच 2-0 से जीता। सउदी अरब में अल नासर की युवा अकादमी के लिए खेलने वाले क्रिस्टियानिन्हो को पहले पुर्तगाल की अंडर 15 टीम में भी शामिल किया गया था।

फिडे विश्व कप-2025 : भारत की उम्मीदों के लिए अहम प्रज्ञानानंदा, अर्जुन और विश्व चैंपियन डी. गुकेश

पणजी (गोवा)। ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा शुरु हो रहे फिडे विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराने की कोशिश करेंगे जिसमें दुनिया की शीर्ष 3 रैंकिंग में काबिज खिलाड़ी अनुपस्थित रहेंगे। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के अलावा अमरीका के हिकारू नाकामुरा और फैबियानो कारूआना की जोड़ी इस टूर्नामैंट में नहीं खेलेगी। विश्व चैंपियन डी. गुकेश और अर्जुन एरिगैसी 20 लाख अमरीकी डॉलर की पुरस्कार राशि के इस प्रतिष्ठित टूर्नामैंट में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। पर सबसे अहम चीज यह है कि इस टूर्नामैंट से 2026 फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामैंट के लिए 3 क्वालीफिकेशन स्थान सुनिश्चित होंगे। कैंडिडेट्स टूर्नामैंट से अगले साल होने वाले विश्व चैंपियनशिप मैच का खिलाड़ी तय होगा। गोवा में अगले 4 हफ्तों तक 80 देशों के 206 शीर्ष शतरंज खिलाड़ी 8 दौर वाले एकल एलिमिनेशन नॉकआउट टूर्नामैंट में हिस्सा लेंगे। प्रत्येक मैच में निश्चित समय में 2 क्लासिकल बाजियां होंगी। देश के पहले ग्रैंडमास्टर और शतरंज के सम्राट श्री विश्वनाथन आनंद के सम्मान में 'विश्वनाथन आनंद कप', फिडे वर्ल्ड कप (ओपन) विजेता के लिए रनिंग ट्रॉफी की शुरुआत की गई है। यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी भारतीय शतरंज की उपलब्धियों और विश्वनाथन आनंद की विरासत का प्रतीक है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक संजोया और सराहा जाएगा।

श्रेयस अय्यर अस्पताल से डिस्चार्ज, रिकवरी के लिए सिडनी में ही रहेंगे

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया कि अय्यर अब सिडनी में मेडिकल सुपरविजन के तहत रिकवरी जारी रखेंगे और पूरी तरह फिट होने के बाद ही भारत लौटेंगे। श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय पेट में गंभीर चोट लगी थी। जांच में पाया गया कि उनके प्लीहा में कट लगने के कारण आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज करते हुए ब्लीडिंग को नियंत्रित किया और एक

मामूली प्रक्रिया के बाद उनकी हालत स्थिर हो गई। बीसीसीआई के चिकित्सा प्रमुख डॉ. अभिजीत सैकिया ने बयान में कहा, 'श्रेयस अय्यर अब स्थिर हैं और अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। सिडनी और भारत के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी रिकवरी से संतुष्ट है। ' बोर्ड ने सिडनी के डॉ. कौरूश हघीगी और उनकी टीम, साथ ही मुंबई के डॉ. दिनशॉ पारदीवाला को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अय्यर को बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराया।ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अय्यर ने दो वनडे में 72 रन बनाए थे, जिसमें एडिलेड वनडे में 61 रनों की जुझारू पारी शामिल थी। इस पारी में उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ शतकीय साझेदारी भी की थी। इस साल अय्यर ने 11 मैचों में 496 रन बनाए हैं, औसत 49.60 और स्ट्राइक रेट 89.53 रहा है। उन्होंने पांच अर्धशतक लगाए हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 79 रन है। इसके अलावा उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 243 रन बनाए थे और भारत के शीर्ष रन-स्कोरर रहे थे।

हाइलो ओपन 2025: उन्नति हुड्डा सेमीफाइनल में, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी क्वार्टर फाइनल में बाहर

एजेंसी

नई दिल्ली। जर्मनी में चल रहे सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट हाइलो ओपन 2025 में भारत की युवा शटलर उन्नति हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 18 वर्षीय उन्नति ने चीनी ताइपे की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लिन हिसियांग ति को सीधे गेम में 22-20, 21-13 से हराया। यह मुकाबला 47 मिनट तक चला। दूसरी ओर, महिला एकल वर्ग में ही भारत की रक्षिता श्री संतोष रामराज को डेनमार्क की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लाइन क्रिस्टोफर्सन से 7-21, 19-21 की हार झेलनी पड़ी। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने पहले गेम में हार के बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन अंततः इंडोनेशिया के खिलाड़ी से 17-21, 21-14, 15-21 से हार गए। यह मैच एक घंटे 14 मिनट तक चला। वहीं, आयुष शेट्टी ने फिनलैंड के काले कोलजोनन के खिलाफ रोमांचक तीन गेमों के मुकाबले में 21-19, 12-21, 20-22 से हार का सामना किया। इस बीच, किरण जॉर्ज भी दूसरे वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई खिलाड़ी जोनेतन क्रिस्टी से 10-21, 16-21 से हार गए। इसके साथ ही भारत का पुरुष एकल अभियान समाप्त हो गया है। अब भारत की उम्मीदें केवल उन्नति हुड्डा पर टिकी हैं, जो सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त पुत्रि कुसुमा वारदानी से भिड़ेंगी।

पेरिस मास्टर्स : नंबर-1 की दौड़ में आगे बढ़े सिनर, सेमीफाइनल में ज्वेरेव से भिड़ंत

एजेंसी

पेरिस। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को सीधे सेटों में हराकर विश्व नंबर-1 रैंकिंग की ओर एक और कदम बढ़ाया। सिनर ने शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में 6-3, 6-3 से जीत दर्ज की और अब सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन एलेक्ज़ेंडर ज्वेरेव से भिड़ेंगे। सिनर का यह लगातार 24वां इनडोर हार्ड कोर्ट मैच जीत है। अगर वे पेरिस में खिताब जीतते हैं, तो वे स्पेन के कार्लोस अल्कराज़ को पीछे छोड़कर फिर से विश्व नंबर-1 बन जाएंगे। अल्कराज़ को दूसरे दौर में कैमरन नॉरी ने चौंकाया था। सिनर ने मैच के बाद कहा, 'इस समय मैं रैंकिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूं। हर दिन एक नई चुनौती होती है, और मैं बस अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। ' 24 वर्षीय सिनर इस सीजन का अपना पांचवां खिताब जीतने की राह पर हैं। इससे पहले वे ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बलडन, चाइना ओपन और विएना ओपन का खिताब जीत चुके हैं। सिनर ने शेल्टन के खिलाफ अपनी सातवीं लगातार जीत दर्ज की है, जबकि उनकी ज्वेरेव के खिलाफ भी पिछली तीन भिड़ंतों में जीत रही है। दूसरी ओर, जर्मनी के तीसरी वरीयता प्राप्त एलेक्ज़ेंडर ज्वेरेव ने दानिल मेदवेदेव को एक रोमांचक मुकाबले में 2-6, 6-3, 7-6 (5) से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ज्वेरेव ने तीसरे सेट में दो

मैच पॉइंट बचाते हुए शानदार वापसी की और मेदवेदेव के खिलाफ लगातार पांच हार का सिलसिला तोड़ा। इससे पहले, कजाखस्तान के एलेक्ज़ेंडर बुब्लिक ने एलेक्स डी मिनौर को हराकर अपने करियर का पहला मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल हासिल किया।

हॉकी इंडिया 7 नवंबर को मनाएगा भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय हॉकी ने 7 नवंबर, 1925 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) से संबद्धता प्राप्त की थी। इसी तारीख ने भारतीय खेल इतिहास में राष्ट्रीय गर्व की कहानी लिखी। तीन साल बाद 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और यहीं से शुरू हुआ हॉकी में भारत का स्वर्ण युग। इन सौ वर्षों में भारतीय हॉकी ने कई उतार-चढ़ाव देखे, जिसमें थे सुनहरे दिन, कठिन दौर और फिर नई उड़ान। 1928 से 1959 का स्वर्णकाल भारत की खेल पहचान बना, 1980 और 90 के दशक ने उसकी परीक्षा ली और फिर आया पुनर्जागरण – टोक्यो 2020 का ऐतिहासिक कांस्य पदक और पेरिस 2024 में एक और पोडियम फिनिश ने नई ऊर्जा भरी। 1975 विश्व कप की जीत और एशियाई खेलों में पुरुषों व महिलाओं की अनगिनत उपलब्धियों ने इस खेल को भारतीय भावना का प्रतीक बना दिया। अब 7 नवंबर 2025 को पूरा देश इस गौरवशाली सफर का उत्सव मनाएगा। मुख्य समारोह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा, जिसकी

शुरुआत एक विशेष प्रदर्शनी मैच खेल मंत्री इलेवन बनाम हॉकी इंडिया मिक्स्ड इलेवन से होगी। इस मैच में पुरुष और महिला खिलाड़ी एक साथ खेलेंगे, जो खेल में समानता और समावेशिता का प्रतीक होगा। इस अवसर पर हॉकी के महान खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। '100 इयर्स ऑफ इंडियन हॉकी' नामक स्मारक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा और एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भारत की हॉकी यात्रा 'एम्स्टर्डम से पेरिस तक' ध्यानचंद की कला से लेकर आधुनिक नायकों के जज्बे तक को जीवंत करेगी। यह उत्सव केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। यह 500 से अधिक जिलों में गूंजेगा, जहां 1,000 से अधिक मैच खेले जाएंगे और करीब 36,000 खिलाड़ी, स्कूलों से लेकर जमीनी स्तर के युवा, वरिष्ठ खिलाड़ी और सामुदायिक टीमें भाग लेंगी।

दबंग दिल्ली केसी ने जीता पीकेएल-12 का खिताब

एजेंसी

नई दिल्ली। दबंग दिल्ली केसी ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन का खिताब जीत लिया है।दबंग दिल्ली ने फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराकर दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद दो या उससे अधिक बार खिताब जीतने वाली दिल्ली तीसरी टीम बन गई है। साथ ही मनप्रीत सिंह के बाद जोगिंदर नरवाल दूसरे ऐसे कोच बने, जिन्होंने कोच और कप्तान के तौर पर खिताब जीता है। दिल्ली की जीत में नीरज नरवाल (9) और अजिंक्य पवार (6) ने अहम भूमिका निभाई। आशू (2) के नहीं चल पाने की स्थिति में दिल्ली के डिफेंस ने भी अच्छा काम किया और 10 अंक बटोरे। फजल अत्राचली पूरे मैच में नहीं चले लेकिन अंतिम मिनट में आदित्य शिंदे (10) का शिकार कर उन्होंने दिल्ली की जीत पक्की कर दी। बहरहाल, आशू पहली ही रेड पर लपके गए और पहले 10 मिनट में खाता नहीं खोल सके लेकिन नीरज नरवाल की बदौलत दिल्ली ने पल्टन को एक बार आलआउट कर बढ़त ले ली लेकिन पल्टन ने इसके बाद दो बार सुपर टैकल की स्थिति का लाभ

लेकर वापसी की। उसके रेडर नहीं चले लेकिन डिफेंस ने एक के मुकाबले चार अंक लेकर उसे मुकाबले में बनाए रखा। पहले क्वार्टर की समाप्ति तक दिल्ली 8-6 से आगे थी जबकि पल्टन के लिए स्थिति बहाल हुई और इस बार अजिंक्य ने दो शिकार के साथ उसे आलआउट कर दिल्ली को 14-8 से आगे कर दिया। आलइन के बाद पंकज ने सुरजीत को छकाया तो नीरज ने सुपर रेड के साथ लीड 7 सुपर टैकल आन था।

ब्रेक के बाद सौरव ने डू ओर डाई रेड पर असलम को लपक पल्टन को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया लेकिन पल्टन न तीसरे सुपर टैकल के साथ स्कोर 8-9 कर दिया। पल्टन के लिए फिर वही की कर दी। हाफटाइम से ठीक पहले आदित्य ने मल्टीप्वांटर के साथ फासला 4 का कर दिया लेकिन अजिंक्य ने इसका जवाब मल्टीप्वांटर से देकर स्कोर 20-14 कर दिया। हाफटाइम के बाद आशू तीसरी बार आउट हुए और फिर दबाव बनाते हुए पल्टन ने दिल्ली के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। फासला घटकर 4 का रह गया था। इस बीच तीन के डिफेंस में आदित्य बिना टच लाबी में गए। इससे दिल्ली ने दो अंक लेकर 30 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 24-18 कर दिया। ब्रेक के बाद दिल्ली के लिए फिर से सुपर टैकल आन हुआ। इस बीच आशू ने बोनस के साथ अपना खाता खोला। फिर तीन के डिफेंस में पंकज डू ओर डाई पर आए और लपक लिए गए। इस दो अंक के साथ दिल्ली ने 8 की लीड ले ली लेकिन आदित्य ने रिनिंग हैंड टच के साथ दिल्ली को दो खिलाड़ी तक सीमित किया और फिर आलआउट लेकर स्कोर 25-28 कर दिया।

जिला स्तरीय ताइक्वांडो रेफरी सेमिनार में 40 ताइक्वांडो प्रशिक्षकों ने सीखी बारीकियां

एजेंसी

मुरादाबाद। पीतलनगरी स्थित थापा ताइक्वांडो एकेडमी में जिला स्तरीय ताइक्वांडो रेफरी सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें जिले के लगभग चालीस ताइक्वांडो प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया । जिला ताइक्वांडो स्पोर्ट्स

एसोसिएशन के सचिव शाहवेज़ अली ने बताया कि इस सेमिनार में ताइक्वांडो खेल के नियमों की जानकारी दी गई और निर्णायक कार्य की बारीकियां सिखाई गई । इस सेमिनार को मुख्य रूप से राष्ट्रीय रेफरी केशव थापा और समिति शर्मा द्वारा संचालन किया गया। इस अवसर पर जिला संघ के सभी पदाधिकारी सहित अरविंद सिंह, संदीप कुमार, अर्जुन थापा, रोहित कुमार आदि उपस्थित रहे ।

ऑस्ट्रेलिया ने हेजलवुड की घातक गेंदबाज़ी की बदौलत भारत को दूसरे टी-20 में 4 विकेट से हराया

एजेंसी

मेलबर्न। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) की उछाल भरी पिच पर अभिषेक शर्मा की शानदार अर्धशतकीय पारी भी भारत को हार से नहीं बचा सकी। जोश हेज़लवुड (3 विकेट पर 13 रन) और साथियों की घातक गेंदबाज़ी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। पहला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। भारत की पारी 18.4 ओवर में 125 रन पर सिमट गई, जिसमें अभिषेक ने 37 गेंदों पर 68 रन बनाए। जवाब में कप्तान मिचेल मार्श (26 गेंदों पर 46 रन) की आक्रामक बल्लेबाज़ी से ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य 13.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। यह भारत की टी20

अंतरराष्ट्रीय इतिहास में गेंदें शेष रहने के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। पावरप्ले में ही चार बल्लेबाज़ पवेलियन लौट गए – यह केवल 10वां मौका था जब भारत ने टी20 में छह ओवरों के भीतर इतने विकेट गंवाए। हेज़लवुड ने टेस्ट जैसी लाइन-लेंथ पर गेंदबाज़ी करते हुए भारतीय टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया। शुभमन गिल (5) और संजू सैमसन (2) सस्ते में आउट हुए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा भी जल्दी चलते बने। भारत का स्कोर तब 6 ओवर में 40/4 था। अभिषेक शर्मा ने एक छोर से आक्रामक अंदाज़ जारी रखा और 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हर्षित राणा (35) के साथ उन्होंने पाँचवें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी की और टीम को 100 के पार पहुँचाया। हालांकि, 16वें ओवर के बाद भारतीय बल्लेबाज़ी फिर लड़खड़ा गई। ज़ेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस ने तेजी से विकेट झटके। अभिषेक 68 रन बनाकर एलिस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए और टीम 125 पर सिमट गई।

रौनक राव और देवांश बिष्ट की घातक गेंदबाजी से श्याम लाल कॉलेज की धमाकेदार जीत

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय अंतर कॉलेज क्रिकेट (पुरुष) टूर्नामेंट 2025-26 में श्याम लाल कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शहीद भगत सिंह कॉलेज (सांध्य) पर 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की। मैच श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज मैदान पर खेला गया। श्याम लाल कॉलेज के तेज गेंदबाज रौनक राव ने कहर बरपाते हुए 23 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि देवांश बिष्ट ने मात्र 14 रन पर 4 विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाज़ों की कमर तोड़ दी। दोनों की घातक गेंदबाजी के सामने शहीद भगत सिंह कॉलेज की टीम मात्र 21.5 ओवर में 80 रन पर सिमट गई। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लेने वाले कप्तान विनय नेगी का फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्याम

लाल कॉलेज ने 15.1 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 81 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया। पारस जायसवाल ने नाबाद 23 रन, जबकि विनय नेगी ने नाबाद 16 रन बनाए। रवि राज ने भी 19 रनों का योगदान दिया।

संक्षिप्त स्कोर:

शहीद भगत सिंह कॉलेज (सांध्य): 21.5 ओवर में 80 रन (भव्य तोमर 26, गौरांश 24, वरुण देव 17; रौनक राव 5/23, देवांश बिष्ट 4/14)।

श्याम लाल कॉलेज: 15.1 ओवर में 3 विकेट पर 81 (पारस जायसवाल 23 नाबाद, विनय नेगी 16 नाबाद, रवि राज 19)।

ऑस्ट्रेलिया टीम को हराना बड़ी उपलब्धि : भुवनेश कुमार

एजेंसी

गौतमबुद्ध नगर। देश की बेटियों ने सात बार की विजेता और अब तक की अजेय ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम का गुरूर तोड़कर तीसरी बार महिला वनडे विश्व कप

के फाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी भुवनेश कुमार ने आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक बहुत बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने कई बार महिला वर्ल्ड कप जीता है। उसे हराना कठिन काम था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहे महिला की हो या पुरुष, उसे हराना एक चुनौती होती है। उन्होंने भारतीय महिला टीम को बधाई दी। वह आज नोएडा पुलिस द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी दौड़ में भाग लेने के लिए आए थे।

हॉकी कोचों के लिए 'एडवांस स्पोर्ट्स साइंस वर्कशॉप' की शुरुआत, श्रीजेश, हरेंद्र सिंह सहित कई दिग्गजों की मौजूदगी

एजेंसी

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 'हॉकी इंडिया-एनसीएसएसआर एडवांस स्पोर्ट्स साइंस वर्कशॉप फॉर हॉकी कोचेस' का शुभारंभ शुक्रवार को इंदिरा गांधी खेल परिसर स्थित नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंसेज एंड रिसर्च में हुआ। यह कार्यशाला 2 नवंबर तक चलेगी। इस तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य खेल विज्ञान के नवीनतम आयामों को हॉकी कोचिंग में समाहित करना है, ताकि कोच खिलाड़ियों के प्रदर्शन और समग्र फिटनेस को वैज्ञानिक तरीकों से बेहतर बना सकें। इसमें देशभर से चयनित 25 एफआईएच लेवल-3 प्रमाणित कोच भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में भारतीय हॉकी के दिग्गज पी.आर. श्रीजेश, हरेंद्र सिंह, गेविन फरेरा, लाजरुस बारला और हॉकी इंडिया के कई अधिकारी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में एनसीएसएसआर के निदेशक ब्रिगेडियर डॉ. बिभु कल्याण नायक ने कहा, 'जब हम भारतीय हॉकी के 100 वर्ष मना रहे हैं, तो यह सही समय है कि खेल विज्ञान को हमारी दैनिक कोचिंग प्रणाली में

शामिल किया जाए। हमने 25 श्रेष्ठ कोचों का चयन इसलिए किया ताकि वे विशेषज्ञों से निकट संवाद के माध्यम से अधिक गहराई से सीख सकें। ' उन्होंने आगे कहा, 'इस कार्यशाला में विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने वाले हॉकी परीक्षण, उनके डाटा विश्लेषण और खिलाड़ियों की अधिकतम क्षमता निकालने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। ' कार्यशाला में प्रदर्शन प्रोफाइलिंग, एथलीट मॉनिटरिंग, बायोमैकेनिक्स, कंडीशनिंग, पोषण, रिकवरी और खेल मनोविज्ञान जैसे विषयों पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। कोचों को प्रयोगशालाओं और मैदान पर प्रायोगिक प्रशिक्षण जैसे यो-यो, स्प्रिंट और एगिलिटी टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। प्रख्यात भारतीय कोच हरेंद्र सिंह ने कहा, 'मैं खेल मंत्रालय और हॉकी इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह पहल की। दस-पंद्रह साल पहले हमारे पास खेल विज्ञान की ऐसी सुविधाएं नहीं थीं। यह भारत में पहला ऐसा कदम है जो भविष्य की पीढ़ी के खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने में मदद करेगा। ' ओलंपियन और पूर्व भारतीय कप्तान पी.आर. श्रीजेश ने कहा, 'अगर हमें 2036 ओलंपिक को लक्ष्य बनाना है, तो हमें अब से ही वैज्ञानिक पद्धतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। जब कोच वैज्ञानिक समझ के साथ काम करेगा, तो वह खिलाड़ियों से प्रदर्शन की सटीक अपेक्षा रख सकेगा – यह खिलाड़ियों और कोच दोनों के लिए लाभदायक होगा। ' कार्यशाला के दौरान कोचों को डेटा-आधारित निर्णय, वास्तविक समय में एथलीट मॉनिटरिंग, मानसिक दृढ़ता, विज़ुअलाइजेशन और सामरिक तैयारी जैसे आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय हॉकी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में कोचों को वैज्ञानिक दृष्टि से सशक्त करना है।

चावल, गेहूं, चीनी, दालें मजबूत; खाद्य तेलों में घट-बढ़

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में चावल की औसत कीमतों में तेजी रही। गेहूं, दालों और चीनी के भाव भी बढ़े। वहीं, खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव देखा गया। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का जनवरी वायदा 55 रिंगिट लुढ़ककर 4,205 रिंगिट प्रति टन रह गया। अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 49.56 डॉलर के भाव बोला गया। घरेलू थोक जिंस बाजारों में चावल की औसत कीमत 14 रुपये बढ़कर 3,858.62 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी। गेहूं तीन रुपये मजबूत हुआ और 2,863.80 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटे की कीमत 11 रुपये की मजबूती के साथ 3,318.69 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी। खाद्य तेलों में मूंगफली तेल की औसत कीमत 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। अन्य खाद्य तेलों में तेजी रही। वनस्पति 64 रुपये मजबूत हुई। सोया तेल 50 रुपये और सूरजमुखी तेल 47 रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुआ। सरसों तेल और पाम ऑयल के भाव में लगभग टिकाव रहा। दाल-दलहनों में तेजी रही। चना दाल 35 रुपये और तुअर दाल 57 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई। उड़द दाल 28 रुपये और मूंग दाल 32 रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुई। मसूर दाल की कीमत 13 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी।

पहली छमाही में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 36.53 प्रतिशत पर

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष पहली छमाही में अप्रैल से सितंबर तक केंद्र का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 36.53 प्रतिशत पर रहा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से सितंबर के दौरान कुल प्राप्तियां 17,30,216 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 49.5 प्रतिशत) रहीं, जबकि कुल व्यय 23,03,339 करोड़ रुपये रहा, जो बजट अनुमान का 45.5 प्रतिशत है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा 5,73,123 करोड़ रुपये रहा। यह बजट अनुमान का 36.53 प्रतिशत है।वित्त वर्ष के पहले पांच महीने में राजकोषीय घाटा 5,98,153 करोड़ रुपये था, जो बजट अनुमान का 38.12 प्रतिशत था। छमाही के दौरान कुल प्राप्तियों में कुल कर राजस्व (केंद्र का हिस्सा) 12,29,370 करोड़ रुपये और गैर-कर राजस्व 4,66,076 करोड़ रुपये रहा। गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति 34,770 करोड़ रुपये रही। कुल व्यय में 17,22,593 करोड़ रुपये राजस्व खाते पर खर्च किये गये और 5,80,746 करोड़ रुपये पूंजी खाते पर खर्च किये गये। राजस्व व्यय में 5,78,182 करोड़ रुपये ब्याज के भुगतान के मद में और 2,02,367 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडियों के मद में खर्च हुये। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष के पहले छह महीने में करों में उनके हिस्से के तौर पर राज्यों को 6,31,751 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये हैं। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 86,948 करोड़ रुपये अधिक है।

रुपया लगातार दूसरे दिन टूटा

मुंबई। विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारतीय पूंजी बाजार से पैसा निकालने के कारण रुपये में 1.50 पैसे की गिरावट देखी गयी और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 88.7050 रुपये प्रति डॉलर बोला गया। इससे पहले भारतीय मुद्रा 47 पैसे की भारी गिरावट के साथ 88.69 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी। रुपये की शुरुआत आज नौ पैसे की मजबूती के साथ 88.60 रुपये प्रति डॉलर पर हुई थी। यह ऊपर 88.7825 रुपये और नीचे 88.5925 रुपये प्रति डॉलर तक गया। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से रुपये पर दबाव रहा।

विदेशी मुद्रा भंडार 6.92 अरब डॉलर घटा

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 6.925 अरब डॉलर घटकर 695.355 अरब डॉलर रह गया। यह 12 सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले, 01 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 9.321 अरब डॉलर घटा था। रिजर्व बैंक के जारी आंकड़े के अनुसार, 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 3.862 अरब डॉलर घटकर 566.548 अरब डॉलर रह गया। इसमें अमेरिकी मुद्रा के अलावा जापानी येन, ब्रितानी पाउंड और यूरो शामिल हैं जिनका मूल्य डॉलर की तुलना में उनकी विनिमय दर के आधार पर तय किया जाता है। स्वर्ण भंडार भी लगातार आठ सप्ताह बढ़ने के बाद 3.010 अरब डॉलर घटकर 105.536 अरब डॉलर रह गया। इसमें गिरावट का मुख्य कारण आलोच्य सप्ताह के दौरान सोने की कीमतों में आयी गिरावट रही जिससे केंद्रीय बैंक के पास पड़े सोने का मूल्य कम हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार के अन्य घटकों में विशेष आहरण अधिकार 5.8 करोड़ डॉलर घटकर 18.664 अरब डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि 60 लाख डॉलर बढ़कर 4.608 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले, 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.496 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 702.28 अरब डॉलर रहा था।

आईपीओ के लिए रिकॉर्ड महीना बना अक्टूबर, 14 आईपीओ के जरिये जुटाये 46,044 करोड़ रुपये

एजेंसी

नई दिल्ली। प्राइमरी मार्केट में अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड 46,044.8 करोड़ रुपये के 14 मेनबोर्ड आईपीओ लॉन्च हुए। इसके पहले ये रिकॉर्ड अक्टूबर 2024 के नाम था। 1 साल पहले अक्टूबर 2024 में 38,689.1 करोड़ रुपये के 6 मेनबोर्ड आईपीओ लॉन्च हुए थे। इस साल अक्टूबर में लॉन्च हुए 14 आईपीओ में साइज के लिहाज से टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ का सबसे अधिक योगदान रहा है। इन दोनों कंपनियां ने आईपीओ के जरिए प्राइमरी मार्केट से 27,119 करोड़ रुपये जुटाये। इस महीने सबसे बड़ा आईपीओ टाटा कैपिटल का था, जिसने 15,512 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च किया था। वहीं, दूसरे स्थान पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ रहा, जिसने 11,607 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च करके प्राइमरी मार्केट

को मजबूती दी थी। इन दोनों बड़े आईपीओ के अलावा आज ही लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का 7,278.02 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च हुआ है। इनके अलावा ओर्कला इंडिया, रुबिकॉन रिसर्च, वीवर्क इंडिया और केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के आईपीओ ने भी इस महीने प्राइमरी मार्केट में अपनी जोरदार चमक दिखाई है। प्राइम डेटाबेस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आईपीओ लॉन्चिंग के मामले में 46,044.8 करोड़ रुपये के मेनबोर्ड आईपीओ पेश करके अक्टूबर 2025 प्राइमरी मार्केट के इतिहास में अव्वल स्थान पर पहुंचने में सफल रहा है। जबकि दूसरे स्थान पर अक्टूबर 2024 रहा, जब कुल 38,689.1 करोड़ रुपये के 6 मेनबोर्ड आईपीओ लॉन्च हुए। तीसरे स्थान पर साल 2021 का नवंबर महीना रहा, जब 35,664.20 करोड़ रुपये के 9 मेनबोर्ड आईपीओ लॉन्च हुए। इसी तरह नवंबर 2024 में 31,145.10 करोड़ रुपये के 8 मेनबोर्ड आईपीएल लॉन्च हुए। वहीं, 8 मेनबोर्ड आईपीओ की लॉन्चिंग से 29,510.8 करोड़ रुपये जुटा कर मई 2022 पांचवें स्थान पर रहा। इसके अलावा 25,438.6 करोड़ रुपये के 15 मेनबोर्ड आईपीओ की लॉन्चिंग के साथ दिसंबर 2024 छठे स्थान पर, 18,823.9 करोड़ रुपये के 3 मेनबोर्ड आईपीओ की लॉन्चिंग के साथ नवंबर 2017 सातवें स्थान पर, 16,668.10 करोड़ रुपये के 7 मेनबोर्ड आईपीओ की लॉन्चिंग के साथ सितंबर 2017 आठवें स्थान पर, 16,246 करोड़ रुपये के 6 मेनबोर्ड आईपीओ लॉन्चिंग के साथ अक्टूबर 2017 नौवें स्थान पर और 15,032.30 करोड़ रुपये के आठ मेनबोर्ड आईपीओ की लॉन्चिंग के साथ मार्च 2018 दसवें स्थान पर रहा।

ट्राई ने ड्राफ्ट प्रस्तावों पर सुझाव देने की तारीख 7 नवंबर तक बढ़ाई

एजेंसी

नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने लोगों और उद्योग संगठनों को अपने दो ड्राफ्ट प्रस्तावों पर राय देने के लिए अब 7 नवंबर तक का समय दिया है। पहले सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। संचार मंत्रालय के अनुसार, ट्राई ने 16 अक्टूबर को 'टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ (बहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2025' और 'द रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन अकाउंटिंग सेपरेशन (संशोधन) विनियम, 2025' जारी किए थे। हितधारकों और उद्योग संगठनों ने इन पर राय देने के लिए अधिक समय मांगा था, जिसके बाद यह समयसीमा बढ़ाई गई है।

एयर इंडिया ने सभी 27 पुराने ए320 विमानों की रेट्रोफिटिंग पूरी की

एजेंसी

नई दिल्ली। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने सभी 27 पुराने ए320 विमानों की रेट्रोफिटिंग पूरी कर ली है। एयरलाइंस ने बताया कि इसके साथ अब उसके बेड़े में शामिल ए320 के सभी 104 विमानों में एक जैसे आधुनिक केबिन हो गये हैं। रेट्रोफिटिंग के दौरान सभी 27 विमानों के केबिन को नये कलेवर में तैयार किया गया है। साथ ही कुछ नये उपकरण भी लगाये गये हैं। रेट्रोफिटिंग के लिए गये सभी 27 ए320 विमान टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण से पहले से एयर इंडिया के बेड़े में थे। अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया के बेड़े में 14 नये ए320 विमान आये। इसके अलावा विस्तार का एयर इंडिया में विलय होने के बाद उसके 63 ए320विमान भी बेड़े का हिस्सा बने हैं।एयर इंडिया ने 40 करोड़ डॉलर की लागत से टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण से पहले के सभी विमानों की रिट्रोफिटिंग की योजना को सितंबर 2024 में अमल में लाना शुरू किया था। एयरलाइंस ने बताया कि वह ए320 विमानों का इस्तेमाल घरेलू और छोटी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर करती है। सभी 104 विमान मिलकर 82 मार्गों पर

3,024 साप्ताहिक उड़ानें भरेंगे। नये केबिन में हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी-ए और यूएसबी-सी पोर्ट हैं। इसके जरिये यात्रा के दौरान मनोरंजन के लिए विस्तार स्ट्रीम की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। एयर इंडिया ने बताया कि अगले साल की शुरुआत में सभी 13 पुराने ए321 विमानों की रेट्रोफिटिंग शुरू होगी। साथ ही विस्तार के भी पुराने ए321 विमानों की रेट्रोफिटिंग होगी। वहीं, पुराने 26 बोइंग बी787-8 विमान फिलहाल रेट्रोफिटिंग के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत स्थित बोइंग के संयंत्र में हैं। ये विमान मई 2025 में वहां भेजे गये थे और 2027 के मध्य तक काम पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, साल 2027 के आरंभ में तेरह बोइंग 777-300ईआर विमानों को रेट्रोफिटिंग के लिए भेजा जायेगा जिसके अक्टूबर 2028 तक पूरा होने की संभावना है।

जापान की मिजुहो बैंक ने जताई ग्रेटर नोएडा में निवेश की इच्छा

एजेंसी

गौतमबुद्ध नगर। जापान के मिजुहो बैंक का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सहित कई अधिकारियों से मिला।विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा व इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की।

प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि जापान के मिजुहो बैंक के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और आईआईटीजीएनएल के प्रबंध निदेशक एनजी रवि कुमार, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्राधिकरण की तरफ से जापानी प्रतिनिधिमंडल के समक्ष ग्रेटर नोएडा और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर की विस्तृत जानकारी दी गई। जापान के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया

कि प्रतिनिधिमंडल ने इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के प्लग एंड प्ले सिस्टम, वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखकर सराहा और यहां निवेश की इच्छा जताई। इस दौरान आईआईटीजीएनएल की पूरी टीम मौजूद रही।

उल्लेखनीय है कि मिजुहो बैंक जापान का एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह है, जो मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा है। यह जापान के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और व्यक्तियों, एमएसएमई, बड़े निगमों और वित्तीय संस्थानों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।

लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट का शिकार हो गया। आज के कारोबार की शुरुआत भी मामूली कमजोरी के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में कुछ देर के लिए तेजी भी आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बिकवाली शुरू हो जाने की वजह से बाजार की चाल में गिरावट आ गई। हालांकि खरीदारों ने कई बार लिवाली का जोर बना कर बाजार को सहारा देने की कोशिश भी की, लेकिन बिकवाली का दबाव इतना अधिक था कि शेयर बाजार संभल नहीं सका। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.55 प्रतिशत और निफ्टी 0.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान मेटल, आईटी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के शेयरों में जम कर बिकवाली होती रही। इसी तरह बैंकिंग, रियल्टी, एफएमसीजी,

ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और टेक इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर डिफेंस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स सेक्टर के शेयरों में खरीदारी होती रही। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.55 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 470.32 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 472.36 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 2.04 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,309 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,784 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,370 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 155 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,800 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई।

दिल्ली सीजीएसटी ने दिल्ली में 32 करोड़ रुपये की फर्जी कर क्रेडिट पकड़ी; एक गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के दिल्ली दक्षिण आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी से इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने के एक मामले का पर्दाफाश किया है और इस मामले में एक कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है। जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार दक्षिण दिल्ली सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय के कर चोरी निरोधक शाखा ने कंपनी के निदेशक को लगभग 31.95 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सक्षम न्यायिक प्राधिकारी ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विज्ञप्ति के अनुसार जांच से पता चला कि कंपनी बिना किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति के केवल चालान के आधार पर धोखाधड़ी से दावे कर इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त कर रही थी। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर जांच में कहा कि फर्म ने बिना किसी वस्तु के वास्तविक लेन-देन के बिना ही इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया और इसके लिए काल्पनिक और कागजी फर्मों के माध्यम से लेन-देन दिखाया।

पांचवीं राष्ट्रीय समुद्री मत्स्योद्योग जनगणना के लिए ऐप जारी, जनगणना तीन नवंबर से

एजेंसी

कोच्चि। केंद्र सरकार समुद्र में मछली पकड़ने के कारोबार में लगे लोगों की पांचवीं राष्ट्रीय जनगणना अगले सप्ताह से शुरू करने जा रही है और इसके लिए घर-घर जा कर मुख्य सूचनाएं एकत्रित करने का काम तीन नवंबर से 18 दिसंबर तक किया जाएगा। मत्स्योद्योग जनगणना में तटीय क्षेत्रों के 5000 से अधिक गांवों और बस्तियों के 12 लाख से अधिक परिवारों की आबादी , उनकी स्थिति और उद्योग से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की अद्यतन सूचनाएं जुटायी जायेंगी ताकि इस क्षेत्र के विकास की सम्यक योजना तय करने में मदद मिले। केंद्र सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने यहां राष्ट्रीय समुद्री मत्स्योद्योग जनगणना 2025 (एमएफसी 2025) में प्रयोग किये जाने वाले व्यास भारत और व्यास-सूत्र डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। मत्स्यपालन , पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि यह राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी के समावेश का एक ऐतिहासिक सूत्रपात है। इसमें सूचनाएं कागज में भरने की परम्परागत विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल ऐप की मदद से इस पूरी प्रक्रिया में लोगों के बारे में विस्तृत, सूक्ष्मतर राष्ट्रीय डाटा संग्रह तैयार होगा जिसमें सटीक भौगोलिक स्थिति का डाटा भी शामिल होगा। पिछली मत्स्योद्योग गणना 2016 में हुई थी। इस गणना में पहली बार अपनाए जा रहे दो डिजिटल ऐप में व्यास-भारत तटीयी मछुआरा बस्तियों में परिवारों और उनके सदस्यों की सूचनाओं की गणना के लिए है।

व्यास-सूत्र ऐप मत्स्य जनगणना में लगे गणनाकर्मियों के काम के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

मत्स्य जनगणना 2025 का वित्तपोषण केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग कर रहा है। आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) इसके लिए नोडल एजेंसी है तथा भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) को इसमें परिचालन भागीदार बनाया गया है।

मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मत्स्य जनगणना में समुद्री मछली पकड़ने के काम में लगे लोगों के 5,000 गांवों में 12 लाख से अधिक घरों के लोगो की गणना की जाएगी। इस काम में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए मोबाइल-आधारित डिजिटल ऐप की मदद से 1,200 से अधिक लैंडिंग केंद्रों, 50 मछली पकड़ने के काम से जुड़े बंदरगाहों, जेटी, बाजारों और प्रसंस्करण संयंत्रों में मछुआरों, मछली पकड़ने की कला, साजो-सामान और बुनियादी ढांचे की स्थिति की गणना भी होगी।

ईडी ने इंदौर के अंबिका सॉल्वेक्स और वर्धमान साल्वेंट की 1.14 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

एजेंसी

भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश में यूको बैंक की लीडरशिप वाले बैंकों से 110.50 करोड़ का लोन लेकर उसका काल्पनिक उपयोग दिखाने और नकद राशि आपस में बांटने, छिपाने के मामले में इंदौर की अंबिका सॉल्वेक्स और वर्धमान साल्वेंट लिमिटेड की 1.14 करोड़ की तीन संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई 29 अक्टूबर को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। ईडी के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने जानकारी दी कि मामले में सीबीआई, एसी-IV, व्यापमं भोपाल द्वारा आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसके बाद सीबीआई द्वारा मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कई अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। ईडी को जांच से पता चला है कि मेसर्स अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड के अधीन काम करने वाली मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूको बैंक के लीडरशिप वाले बैंकों के एक संघ से साख पत्र (एलसी) और निर्यात पैकिंग क्रेडिट (ईपीसी) के माध्यम से लगभग 110.50 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी से लिए। हालांकि दस्तावेजों में इस राशि का उपयोग वैध व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए दिखाया गया था। जांच में पता चला कि कोई वास्तविक खरीद या निर्यात नहीं किया गया था। इसके बजाय व्यवसायिक गतिविधियों का झूठा आभास पैदा करने के लिए धनराशि को अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड की विभिन्न समूह संस्थाओं के माध्यम से आपस में लेन-देन में भेजा गया था। ऋण की आय को बाद में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट फायदे के लिए डायवर्ट किया गया, जिसमें अचल संपत्ति में इन्वेस्ट और समूह के अधीनस्थ काम करने वाली संबंधित कंपनियों, फर्मों और बेनामी संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से नकदी का ट्रांजेक्शन किया गया था। इसके लिए डायवर्ट धनराशि को छिपाया गया और उसका उपयोग किया गया। ईडी ने मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड और मेसर्स वर्धमान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इंदौर स्थित 1.14 करोड़ रुपये लागत की तीन अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी द्वारा इस मामले में पहले भी इस समूह के कई व्यक्तियों और संस्थाओं की 26.53 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क की जा चुकी है।

आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में अर्थव्यवस्था पर मंथन

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल की राजस्थान के उदयपुर में हुई बैठक में वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य पर गहन

विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय बैंक ने बताया कि बैठक में घरेलू अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के साथ मौजूदा भू-राजनैतिक स्थिति और वित्तीय बाजार में बन रही परिस्थितियों तथा संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गयी। निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियों के कामकाज की समीक्षा की। जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) और ग्राहक शिक्षा एवं संरक्षा विभाग जैसे चुनिंदा सरकारी विभागों के काम का आंकलन भी किया गया। बैठक में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे., डॉ पूनम गुप्ता, शीरीश चंद्र मुमु और केंद्रीय बैंक के अन्य निदेशक शामिल थे।

शादी सीजन 2025 में देशभर में होने वाली 46 लाख शादियों से 6.5 लाख करोड़ रुपये का होगा व्यापार : कैट

नई दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इस शादी सीजन के दौरान देशभर में लगभग 46 लाख शादियां होने का अनुमान जताया है, जिनसे कुल 6.50 लाख करोड़ रुपये का व्यापार होगा। कारोबारी संगठन कैट की अनुसंधान शाखा कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (सीआरटीडीएस) के अध्ययन से यह बात सामने आई है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने जारी एक बयान में बताया कि कैट की अनुसंधान शाखा कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (सीआरटीडीएस) ने शादियों को लेकर इस बार एक खास अनुमान लगाया है। इस अनुमान के मुताबिक आगामी शादी सीजन 1 नवंबर से 14 दिसंबर, 2025 के दौरान देशभर में लगभग 46 लाख शादियां होंगी, जिनसे कुल 6.50 लाख करोड़ का व्यापार होगा। प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि सीआरटीडीएस ने यह व्यापक अध्ययन 15 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच देश के 75 प्रमुख शहरों में किया था। इस अध्ययन से पता चला कि भारत की ÷वेडिंग इकॉनमी÷ घरेलू व्यापार का एक मजबूत स्तंभ है, जो परंपरा, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का संगम है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ÷वोकल फॉर लोकल÷ विजन के अनुरूप है।

कैट की अनुसंधान शाखा कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी की अध्ययन के अनुसारः-

देशभर में कुल शादियां :- 46 लाख

अनुमानित व्यापारः 6.50 लाख करोड़ रुपये

दिल्ली में शादियां :- 4.8 लाख

दिल्ली का योगदान :- 1.8 लाख करोड़ रुपये

तुलनात्मक रूप से 2024 में 48 लाख शादियों से 5.90 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था। 2023 में 38 लाख शादियों से 4.74 लाख करोड़ रुपये और 2022 में 32 लाख शादियों से 3.75 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था।

कैट महामंत्री ने कहा कि इस वर्ष शादियों की संख्या लगभग पिछले वर्ष के बराबर है, लेकिन प्रति शादी खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका कारण बढ़ती आय, कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि और त्योहारी सीजन में उपभोक्ता विश्वास का बढ़ना शामिल है। उन्होंने कहा कि अध्ययन में यह भी सामने आया कि अब शादी से जुड़े 70 फीसदी से अधिक सामान भारतीय निर्मित हैं, जैसे परिधान, आभूषण, सजावट सामग्री, बर्तन, कैटरिंग आइटम आदि प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कैट के वोकल फॉर लोकल वेडिंग्स अभियान ने चीनी लाइटिंग, कृत्रिम सजावट और गिफ्ट एक्सेसरी जैसे आयातित उत्पादों की मौजूदगी को काफी घटा दिया है। पारंपरिक कारीगरों, ज्वैलर्स और वस्त्र उत्पादकों को भारी ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे भारत की स्थानीय विनिर्माण क्षमता और हस्तकला को नया बल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 6.5 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित शादी खर्च में से वस्त्र एवं साड़ियां 10 फीसदी, आभूषण 15 फीसदी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल्स 5 फीसदी, सूखे मेवे एवं मिठाई 5 फीसदी, किराना एवं सब्जियां 5 फीसदी, गिफ्ट आइटम 4 फीसदी, अन्य सामान 6 फीसदी हिस्सा लेंगे। वहीं, सेवाओं के क्षेत्र में इवेंट मैनेजमेंट 5 फीसदी, कैटरिंग 10 फीसदी, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी 2 फीसदी, यात्रा एवं आतिथ्य 3 फीसदी, पुष्प सजावट 4 फीसदी, म्यूजिकल ग्रुप्स 3 फीसदी, लाइट एंड साउंड 3 फीसदी तथा अन्य सेवाएं 3 फीसदी योगदान देंगी।क्षेत्रवार विश्लेषण में खंडेलवाल ने बताया कि नई दिल्ली में 4.8 लाख शादियों से 1.8 लाख रुपये करोड़ का व्यापार होने का अनुमान है, जिसमें सबसे अधिक खर्च आभूषण, फैशन और वेन्यू पर होगा।

तंजानिया में विपक्ष का दावा: चुनावी विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों मौत

एजेंसी

दार अस सलाम। तंजानिया की मुख्य विपक्षी पार्टी 'चाडेमा' ने आरोप लगाया कि विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव के बाद देश में पिछले तीन दिनों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों में सुरक्षाबलों के हाथों करीब 700 लोग मारे गए हैं। हालांकि सरकार ने इसे 'अतिशयोक्तिपूर्ण' बयान बताकर खारिज कर दिया है।राष्ट्रपति चुनावों के लिए बुधवार के मतदान के बाद हिंसा उस समय भड़की, जब राष्ट्रपति समिया सुहुलु हसन ने मुख्यरूप से जंजीबार में 78फीसदी से अधिक वोट हासिल किए। इससे पहले 'चाडेमा' और 'एक्ट-वजालेंदो' दलों के उम्मीदवारों को नामांकन से रोक दिया गया, जिससे दार अस सलाम और अन्य शहरों में झड़पें हुईं। खबरों के मुताबिक पुलिस ने हिंसा पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी।इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और गोलीबारी की घटनाएं भी हुईं। साथ ही सेना को 'स्थिति नियंत्रित' करने के लिए तैनात किया गया। एक राजनयिक स्रोत ने दर्जनों मौतों की पुष्टि की, लेकिन आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कम से कम 10 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए इन घटनाओं पर चिंता जताई है। उधर, यूरोपीय सांसदों ने भी इस चुनाव को 'धोखाधड़ी' और दमन से भरा बताया।

फ्लोरिडा में जेटब्लू के विमान की आपात लैंडिंग, कई यात्री घायल

फ्लोरिडा। मेक्सिको से न्यू जर्सी जा रहे जेटब्लू के एक विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। इस दौरान कई यात्री घायल हो गए। जेटब्लू ने बयान में कहा कि विमान फ्लोरिडा के टैम्पा में उतरा। इसके बाद कुछ यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार जेटब्लू का विमान (एयरबस ए320) न्यूर्क लिबर्टी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ था। इसकी आपात लैंडिंग करानी पड़ी। संघीय उड्डयन प्रशासन और जेटब्लू ने जांच किए जाने तक उसे रोक दिया है। जेटब्लू ने कहा कि आपात लैंडिंग के समय विमान कैनकन से नेवार्क जा रहा था। पायलटों ने हवाई यातायात नियंत्रकों को बताया कि कम से कम तीन यात्री घायल हुए हैं और उन्हें चोट भी आई है। उल्लेखनीय है कि 18 मिलियन से अधिक की अनुमानित जनसंख्या के साथ फ्लोरिडा दक्षिण-पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। दक्षिण में टेक्सास के बाद दूसरा और संयुक्त राज्य अमेरिका में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।

अमेरिका में मरीन कॉर्प्स का अधिकारी 12 साल की लड़की के अपहरण में गिरफ्तार

वाशिंगटन। अमेरिका की मरीन कॉर्प्स के एक अधिकारी को एक 12 साल की लड़की का यौन शोषण के इरादे से अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मरीन कॉर्प्स अमेरिकी सशस्त्र बल की एक विशिष्ट शाखा है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने बयान में कहा कि मरीन कॉर्प्स का अधिकारी 24 वर्षीय विलियम रिचर्ड रॉय उत्तरी कैरोलिना के लेज्यून कैंप में तैनात था। यह पिछले हफ्ते शिकागो गया था। वहां पार्क में पीड़ित लड़की से मिला और फिर उसे होटल में ले गया। उसे रात भर होटल में रखा। इसके बाद विलियम रिचर्ड उत्तरी कैरोलिना के डरहम जाने वाली बस में सवार हो गया। एफबीआई के बयान के अनुसार लड़की की दादी ने पिछले शुक्रवार को पीड़ित के लापता होने की प्रथम सूचना दी। एफबीआई ने कहा कि रॉय को रविवार को डरहम पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की मिल गई है। इस अधिकारी पर तीन आरोप हैं, जिनमें एक नाबालिग को अवैध यौन कृत्य के लिए राज्य की सीमा पार ले जाना और बहलाना-फुसलाना शामिल है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने अपने अधिकारी की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया।

ताइवान चीन के 'एक देश, दो व्यवस्था' को ठुकराता है: राष्ट्रपति लाई चिंग-ते

ताइपे। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा कि उनका देश चीन के 'एक देश, दो व्यवस्था' मॉडल को कभी स्वीकार नहीं करेगा तथा अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखेगा। यह बयान चीन की ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने की ताजा कोशिशों के बीच आया है, जहां चीन ने इस साल इसके खिलाफ बल प्रयोग की संभावना से भी 'इंकार नहीं' नहीं किया है। उत्तरी ताइवान के हुकोउ सैन्य अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए लाई ने कहा, 'सच्ची शांति केवल ताकत से ही आ सकती है। आक्रामण के दावों को मान लेना और संप्रभुता छोड़ना शांति नहीं ला सकता। हमें गरिमा और दृढ़ता से वर्तमान स्थिति बनाए रखनी चाहिए। जबरदस्ती होने वाले एकीकरण, आक्रमण और विलय का हमें विरोध करना होगा।' उन्होंने कहा, 'हम 'एक देश, दो व्यवस्था' को खारिज करते हैं क्योंकि हम हमेशा अपनी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाएंगे।' गौरतलब है कि चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है और लाई को 'अलगाववादी' कहता है। इस सप्ताह चीन के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अगर ताइवान हांगकांग-मकाऊ जैसी स्वायत्तता स्वीकार करता है, तो उसके साथ नरम व्यवहार होगा। लेकिन ताइवान के किसी बड़े राजनीतिक दल ने चीन की इस नीति का समर्थन नहीं किया है।

प्रधानमंत्री ने मीडिया के संपादकों से की वार्ता, चुनाव होने पर संदेह न करने की अपील की

एजेंसी

काठमांडू। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जनता और राजनीतिक दलों से 5 मार्च 2026 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनावों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता पर संदेह न करने की अपील की। प्रधानमंत्री निवास में विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादकों के साथ बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री कार्की ने जोर देकर कहा कि सरकार शांतिपूर्ण और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवाद और सहमति के माध्यम से काम कर रही है। प्रधानमंत्री कार्की ने आश्वासन दिया कि सुरक्षा व्यवस्था नियंत्रण में है और तैयारियां योजना के अनुसार जारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा तंत्र चुनाव तैयारियों को पूरा करने में लगे हुए हैं। बैठक में मौजूद संपादकों ने सुरक्षा चुनौतियों के कारण चुनाव में संभावित देरी को लेकर चिंता जताई, जिनमें पुलिस का कम मनोबल, 9 सितंबर को अशांति के दौरान हथियार लूटना, क़ैदियों का भाग जाना और पारंपरिक राजनीतिक शक्तियों द्वारा संभावित व्यवधान शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि इस घटना के दौरान लूटे गए लगभग 1,200 हथियारों में से आधे तो पहले ही बरामद हो चुके हैं, जबकि बाकी के स्थान का पता चल चुका है और जल्द ही उन्हें भी पुनः हासिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 9 सितंबर को आगजनी में लगभग 150 पुलिस हथियार नष्ट हो गए थे। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि उनकी सरकार जेन-जी आंदोलन की मांगों के अनुरूप सुशासन उपाय लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की कि नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर चर्चा शुरू हो चुकी है, हालांकि कानूनी और प्रक्रियागत बाधाएं अभी बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी हैं। आगे भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कार्की जेन-ज़ेड प्रतिनिधियों के साथ संवाद जारी रखेंगी।

नेपाल में भारी हिमपात के बीच पांच दिनों से फंसे 11 विदेशी पर्यटकों को 9 घंटे की मशक्कत के बाद बचाया गया

एजेंसी

काठमांडू। भारी हिमपात और लगातार वर्षा के कारण पाँच दिनों से मनांग स्थित तिलिचो बेस कैंप में फँसे 11 विदेशी पर्यटकों को सशस्त्र पुलिस बल ने 9 घंटे के प्रयास के बाद सफलतापूर्वक बचाया है। सशस्त्र पुलिस बल के प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापा के अनुसार, सशस्त्र पुलिस बल के माउंटेन रेस्क्यू ट्रेनिंग स्कूल (एमआरटीएस) से भेजी गई माउंटेन रेस्क्यू टीम ने इन सभी को सुरक्षित रूप से बचाया। बचाए गए पर्यटकों में एक व्यक्ति के पैर में चोट लगी है। इनमें 9 वर्षीय बालक और एक बीमार महिला है। बाकी सभी सामान्य स्थिति में हैं।

थापा ने बताया कि सभी की ऑक्सीजन लेवल कम है। इन विदेशी पर्यटकों का बचाव अभियान प्रतिकूल परिस्थितियों, संकीर्ण, ढलानदार और दो फीट बर्फ जमी कठिन रास्ते से होकर 9 घंटे के प्रयास के बाद सफल हुआ। पर्वतीय बचाव प्रशिक्षण संस्थान से एसपी टोपबहादुर डाँगी के नेतृत्व में मेडिकल और माउंटेन रेस्क्यू टीम ने विशेष पर्वतीय बचाव उपकरणों का उपयोग कर इस जोखिमपूर्ण कार्य को पूरा किया। पर्यटकों की स्थिति सामान्य बताई गई है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है।

जेलेंस्की का 'एक्स' पर पोस्ट : रूस पर नए प्रतिबंधों की योजना

एजेंसी

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस पर नए और सख्त प्रतिबंधों की एक योजना का ऐलान किया जिससे रूसी तेल कंपनियों को अगले साल 50 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर इस योजना का ऐलान किया।जेलेंस्की ने कहा कि रूस की तेल कंपनियों को अगले साल प्रतिबंधों से 50 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसे और बढ़ाया जा सकता है। जेलेंस्की ने पोस्ट में बताया कि उन्होंने आज रूस पर आगे और प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। इसमें साझेदार देशों के प्रतिबंध (जिनके लिए यूक्रेन सुझाव देता है), यूक्रेन के अपने प्रतिबंध (जो यूरोपीय देशों के साथ मेल खाते हैं), और भविष्य में देर तक चलने वालें प्रतिबंध शामिल हैं, जो सीधे और तेजी से असर करते हैं। पोस्ट में उन्होंने तीन मुख्य बिंदुओं की बात कही। उन्होंने कहा कि मिसाइलों और अन्य हथियारों का उत्पादन करने वाले रूस के कई कारखानें, जो अभी वैश्विक प्रतिबंधों के दायरे में नहीं हैं, प्रतिबंधों को स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन जैसे गैर-ईयू देशों का समर्थन), जापान, कनाडा और अमेरिका के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। योजना के आखिरी

'हम इसे ठीक करेंगे।' योजना के दूसरे कदम की ओर इशारा करते हुए उन्होंने सहयोगी देशों के साथ मिलकर मौजूदा प्रतिबंधों को समन्वित करने के लिए 'काम' करने की मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों का 'संयुक्त प्रभाव' सबसे ज्यादा असरकारक होता है। इसके लिए जी-7 देशों, समूचे यूरोप (यूरोपीय संघ (ईयू) के और तीसरे कदम के तौर में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा(एसबीयू) और विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुखों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ भविष्य में लंबे समय तक चलने वाले प्रतिबंधों के लिए 'प्राथमिक लक्ष्यों' का चयन किया शामिल जाना है। उन्होंने जोर देकर कहा, 'हम निश्चित रूप से इन्हें लागू करेंगे।'

कैरिबियाई द्वीप के देशो में तूफान 'मेलिसा' की तबाही, मृतकों का आंकड़ा 50 पहुंचा

एजेंसी

वाशिंगटन। कैरिबियाई द्वीपों पर तूफान 'मेलिसा' के कारण जानमाल को हुए भारी नुकसान में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। यह तूफान अटलांटिक के सबसे तेज तूफानों में से एक था। खबरों के मुताबिक मेलिसा की चपेट में आए हैती में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां 30 लोग मारे गए जबकि 20 अन्य लापता हैं। पेटीट-गोएव शहर में नदी का बांध टूटने से 23 लोग डूब गए, जिनमें 10 बच्चे शामिल थे। यह शहर राजधानी से 40 मील दूर है। राहत एवं बचाव कार्य में लगें लोगों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इस बीच जमैका में इसके कारण 19 व्यक्तियों की मौत हो गई है जबकि डोमिनिकन गणराज्य में 2 लोग मारे गए। हालांकि क्यूबा में तूफान में मरने वालें लोगों की संख्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वहां भारी बारिश से सैकड़ों गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। तूफान के कारण तेज हवाओं से बिजली आपूर्ति बिलकुल ठप है और लाखों लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। लगभग समूचे द्वीप

समूह के विभिन्न देशों में घर क्षतिग्रस्त हैं, सड़कें अवरुद्ध हैं और तूफान के कारण हुई बारिश में विस्तृत क्षेत्र जलमग्न हैं। जमैका के 6 जिलों में 170 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। क्यूबा में 200 से ज्यादा जगहों का बाढ़ और भूस्खलन के कारण संपर्क टूटा हुआ है। हैती में हजारों लोग अस्थायी आश्रयों में रहने को विवश हैं। खबरों के मुताबिक बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बिजली न होने और सड़कों के बंद होने से इसमें बाधा आ रही है। जमैका में मृतकों के शवों को हेलीकॉप्टर की मदद से बरामद किया जा रहा है। क्यूबा के कई गांव अभी भी अलग-थलग हैं। इस बीच जमैका की शिक्षा मंत्री डाना डिक्सन ने कहा, 'तूफान ने पूरे जमैका को 'तोड़-मरोड़' कर रख दिया है, लेकिन हम मजबूत हैं। हम हर जमैकावासी तक पहुंचेंगे और मदद देंगे।' इस बीच सूत्रों ने बताया कि यह तूफान अब बरमूडा से दूर जा रहा है।

रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं अमेरिका के बीच रक्षा 'फ्रेमवर्क' समझौते पर हस्ताक्षर

एजेंसी

कुआलालंपुर। भारत और अमेरिका ने आगामी दस वर्षो के लिए रक्षा क्षेत्र में समन्वय, सूचनाओं के आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए यहां एक महत्वपूर्ण रक्षा 'फ्रेमवर्क' समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर यहां दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (आसियान)के रक्षा मंत्रियों बैठक के इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष पीटर हेगसेथ के बीच मुलाकात के दौरान हस्ताक्षर किये गये। सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस बाबत खबर साझा करते हुए सिंह ने इस समझौते की पुष्टि करते हुए हेगसेथ के साथ अपनी बैठक को काफी 'उपयोगी' बताया। उन्होंने कहा,मेरी यहां अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ के एक बेहद ' सार्थक' बैठक हुई जिसमें हमने दस वर्षीय 'भारत अमेरिका रक्षा साझीदारी ढांचागत समझौते' पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशो के बीच पहले से ही मजबूत रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ कर एक नए युग की शुरूआत करेगा।

उन्होंने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय रक्षा संबधो के सभी आयामों के बारे में नीति निर्धारित करने में मदद देगा। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा, समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी का संकेत है जिससे इस दशक में हमारी साझीदारी के नए युग का आरंभ होगा। उन्होंने कहा कि यह साझीदारी स्वतंत्र, निष्पक्ष और 'नियम' आधारित भारत- प्रशांत क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी 'एक्स' पर इस बाबत बयान साझा करते हुए कहा, मैंने अभी-अभी राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की। हमने दस-वर्षीय अमेरिका-भारत रक्षा ढाँचागत सहयोग संबधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हमारी रक्षा साझीदारी को आगे बढ़ाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और प्रतिरोध की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि दोनों देश समन्वय, सूचना साझाकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के रक्षा संबंध पहले कभी इतने मज़बूत नहीं रहे थे। इससे पहले सिंह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 12वीं बैठक (एडीएमएम-प्लस) में भाग लेने के लिए अपनी दो दिवसीय यात्रा के तहत मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे । गुरुवार को यहां पहुंचने पर सिंह का स्थानीय अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यह बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसमें भारत आसियान देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का प्रयास करेगा। गौरतलब है कि सिंह की यह यात्रा ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब भारत-आसियान संबंधों को नए आयाम प्रदान करने के लिए जाने के लिए रणनीतिक वार्ताएं हो रही हैं। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह बैठक में आसियान देशों के साथ आतंकवाद विरोधी उपायों, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण पर जोर देंगे। भारत ने हाल के वर्षों में आसियान के साथ रक्षा अभ्यासों और हथियारों के हस्तांतरण को बढ़ावा दिया है, जो इस बैठक के प्रमुख एजेंडे का हिस्सा हैं। सिंह ने एक्स पर अपनी यात्रा की जानकारी साझा करते हुए कहा कि आसियान-भारत बैठकें रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का माध्यम बनेगी। उनकी यह यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के अनुरूप है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को प्राथमिकता देती है।

नाइजीरिया में खतरे में है ईसाई धर्म- ट्रंप का बड़ा दावा, विशेष निगरानी का आदेश

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि नाइजीरिया में ईसाई समुदाय के लोग अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं।उन्होंने इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों पर ईसाइयों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए नाइजीरिया की विशेष निगरानी करने को कहा है।ट्रंप ने कहा कि जब ईसाई समुदाय से जुड़े लोग ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं तो अमेरेका चुप नहीं बैठा रह सकता। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट साझा कर कहा है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि हजारों की संख्या में ईसाई मारे जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को जिम्मेदार ठहराते हुए नाइजीरिया की विशेष निगरानी का आदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कांग्रेस सांसद रिले मूर, अध्यक्ष टॉम कोल सिनेट कमेटी के साथ मिलकर इस मामले की जाँच कर रिपोर्ट देने का अनुरोध किया। अमेरिका विशेष निगरानी की श्रेणी में उन देशों को रखता है जो उसके मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में संलिप्त हैं।

जर्मनी के दक्षिणपंथी 'एएफडी' दल ने ट्रंप प्रशासन के साथ गठजोड़ मजबूत किया

एजेंसी

बर्लिन। जर्मनी में घरेलू बहिष्कार झेल रहे चरमपंथी 'एएफडी' दल के अमेरिकी प्रशासन के 'मागा' (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) नेताओं से गठजोड़ की खबरें हैं। हाल ही में एएफडी ने अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से महत्वपूर्ण बैठकें कीं, जो आप्रवासन-विरोधी नीतियों और राजनीतिक दमन पर दोनों के बीच सहमति दर्शाता है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस महीने अमेरिका के मैनहट्टन में 'न्यूयॉर्क यंग रिपब्लिकन क्लब' के एक समारोह में एएफडी सांसद जान वेंजेल शिमट और के गॉटस्कॉल्क ने जर्मन राष्ट्रगान की नाजी-युग की वह पंक्ति गाई जिसपर अब रोक लगी हुई है। उसमें 'जर्मनी, जर्मनी सबसे ऊपर।' का उल्लेख है। हालांकि शिमट ने नाजियों से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया

है। इस बीच गॉटस्कॉल्क ने आरोप लगायाा, 'हमारे पास अब लोकतंत्र ही नहीं बचा।' एएफडी जर्मनी में अपने बहिष्कार को चुनौती देने के लिए अमेरिकी वैधता चाहता है। सर्वेक्षणों में एएफडी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ' की 'क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन' कंजर्वेटिव पार्टी को चुनौती दे रही है, और देश के आगामी चुनावों में पहली बार सत्ता हासिल कर सकती है। ट्रंप के पुनर्निर्वाचन से पहले ही एएफडी ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। फरवरी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वैंस ने एएफडी नेता एलिस वीडेल से मुलाकात की थी और बाद में मई में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एएफडी को चरमपंथी घोषित करने को 'छिपा अत्याचार' कहा। एएफडी को देश में वायरटैपिंग, सार्वजनिक सेवा से बहिष्कार और अलोकतांत्रिक कदमों से शिकायत हैं। हालांकि खुफिया एजेंसी ने एएफडी को नस्लवादी और मुस्लिम-विरोधी घोषित किया है। इस बीच एफडी के नेता जोआचिम पॉल ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने उनके मामले को ध्यान से सुना, लेकिन इस बाबत कोई प्रत्यक्ष मदद नहीं दी।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन -जहाजों पर अमेरिकी सैन्य हमले अस्वीकार्य हैं

एजेंसी

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने पहली बार अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि दक्षिण अमेरिका से कथित तौर पर अवैध 'ड्रग्स' ले जा रहे जहाजों पर अमेरिकी सैन्य हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने मानवाधिकार संगठन के प्रमुख वोल्कर टर्क के हवाले से यह बात कही। टर्क ने इन हमलों की जाँच की माँग की है। उन्होंने कहा, ये हमले और इनके कारण लोगों के मारे जाने की घटनाएं अस्वीकार्य है।

टर्क के मुताबिक सितंबर की शुरुआत से इस क्षेत्र में नौकाओं पर हुए हमलों में कथित तौर पर 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के किसी संगठन ने पहली बार इस बाबत अमेरिका की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की है।

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौकाओं पर हमलों को देश में 'ड्रग्स' की तस्करी रोकने के लिए एक आवश्यक कार्रवाई बताते हुए उचित ठहराया है। इस बीच टर्क का मानना है कि कैरिबियन और प्रशांत महासागर में नौकाओं पर अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा, ये हमले और उनकी बढ़ती मानवीय क्षति अस्वीकार्य है। अमेरिका को ऐसे हमले रोकने चाहिए और इन नावों पर सवार लोगों की कानूनी दायरे के बाहर जाकर हत्या करने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। टर्क ने इन प्रयासों को नशीली दवाओं और आतंकवाद विरोधी अभियान के रूप में प्रस्तुत करने के अमेरिकी स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई कानून प्रवर्तन का मामला है, जो 'घातक' बल का उपयोग सावधानीपूर्वक एवं नियंत्रित रूप से किया जाता है ।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृहमंत्री लेखक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

एजेंसी

काठमांडू। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने पासपोर्ट निलंबन और सरकार की अनुमति के बिना काठमांडू से बाहर जाने पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ दायर

रिट याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश नृपध्वज निरौला की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है, लेकिन सरकार और जांच आयोग को इस बारे में 15 दिनों के भीतर कारण सहित लिखित जवाब पेश करने को कहा है। जेन-जी आंदोलन के दौरान हुए दमन और अगले दिन हुई आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग की सिफारिश पर अंतरिम सरकार ने ओली, लेखक और काठमांडू के तत्कालीन मुख्य जिला अधिकारी छविराज रिजाल का पासपोर्ट निलंबित करते हुए उनकी अनुमति के बिना काठमांडू से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी।

ब्रिटेन के राजा ने छोटे भाई से शाही उपाधि, सम्मान और विशेषाधिकार छीने, विंडसर आवास से बाहर किया

एजेंसी

लंदन। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स (तृतीय) ने आखिरकार अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू (65) से उनकी बची हुई सभी शाही उपाधि, सम्मान और विशेषाधिकार छीन लिए। साथ ही उन्हें विंडसर स्थित आवास रॉयल लॉज से बाहर निकलने का आदेश भी दिया है। किंग चार्ल्स को जन दबाव के आगे झुकते हुए यह घोषणा करनी पड़ी। उन्हें यह कठोर फैसला दिवंगत बाल यौन शोषण के आरोपित जेफरी एप्स्टीन से ड्यूक ऑफ यॉर्क के संबंधों पर दोबारा उठे विवादों के बाद करना पड़ा। पीड़ित वर्जीनिया गिफ्रे के परिवार ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए इसे अपनी जीत बताया है। द इंडिपेंडेंट अखबार की इस घटनाक्रम पर केंद्रित रिपोर्ट के अनुसार वर्जीनिया गिफ्रे के संस्मरण के प्रकाशन के बाद राजा पर भी कई तरह के सवाल उठे। संस्मरण में आरोप लगाया कि प्रिंस एंड्रयू ने कम उम्र (नाबालिग) में उनका यौन शोषण किया गया। 41 वर्षीय पीड़ित गिफ्रे का ऑस्ट्रेलिया में इसी साल अप्रैल में निधन हो चुका है। उनके आत्महत्या करने के बाद राजा पर कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ा। हालांकि प्रिंस एंड्रयू ने इन आरोपों को कड़ाई से नकारा। बड़े भाई और राजा के फैसले के बाद अब प्रिंस एंड्रयू को आम नागरिक का दर्जा प्राप्त होगा। बकिंघम पैलेस के बयान के अनुसार प्रिंस एंड्रयू अब आधिकारिक तौर पर एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर के नाम से जाने जाएंगे। उन्हें रॉयल लॉज के स्थान पर कहीं और निजी आवास में रहना होगा। बकिंघम पैलेस ने स्वीकार किया कि निर्णय लने में देर हुई है। राजा के फैसले पर गिफ्रे के परिवार ने कहा कि यह उनके लिए बड़ी जीत है। यह सच की जीत है। परिवार ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने असाधारण साहस से एक ब्रिटिश राजकुमार को हरा दिया। परिवार ने घोषणा की है कि हम वर्जीनिया की लड़ाई जारी रखेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक सभी आरोपितों को दंड नहीं मिल जाता। अब माना जा रहा है कि एंड्रयू सैंड्रिंघम एस्टेट की एक संपत्ति में रहने चले जाएंगे। राजा के बयान के अनुसार आज प्रिंस एंड्रयू की शैली, उपाधियों और सम्मानों को हटाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रिंस एंड्रयू अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाने जाएंगे। रॉयल लॉज के की लीज ने अब तक उन्हें रहने लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। अब लीज छोड़ने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया है और वह वैकल्पिक निजी आवास में चले जाएंगे। उनकी निंदा आवश्यक है, भले ही वह अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार करते रहे हों। मेरी संवेदनाएं संवेदनाएं सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के पीड़ितों के साथ हैं और रहेगीं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, बयान में यह भी जोड़ा गया कि विंडसर कैसल के पास स्थित उनका 30 कमरों वाला भव्य निवास रॉयल लॉज अब उनके स्वामित्व में नहीं रहेगा। वे किसी निजी आवास सैंडरिंगहम एस्टेट (नॉरफॉक) में शिफ्ट होंगे। महल ने कहा कि ये कदम आवश्यक थे। बयान के अंत में किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने यौन शोषण पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस निर्णय के नैतिक आधार को रेखांकित किया। विवाद के बाद उठे तूफान को ब्रिटिश राजघराने के आधुनिक इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक बताया गया है। ग्रिफे के आरोपों के बाद एंड्रयू की प्रतिष्ठा ध्वस्त हो गई। एंड्रयू ने 2022 में इस मामले का निपटारा करने के लिए भारी भरकम धनराशि दी थी। हाल ही में वर्जीनिया की किताब नोबॉडीज गर्ल का प्रकाशन हुआ। इसमें उन्होंने अपने आरोपों का विस्तार से जिक्र किया। राजा के फैसले के बाद प्रिंस एंड्रयू ने अपना सब कुछ गंवा दिया। प्रिंस एंड्रयू के पास जन्म और सेवा दोनों के आधार पर कई प्रतिष्ठित उपाधि थीं। 1960 में जन्म के समय उन्हें हिज रॉयल हाईनेस प्रिंस एंड्रयू अल्बर्ट क्रिश्चियन एडवर्ड ऑफ यॉर्क के रूप में जाना गया। रानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के दूसरे बेटे होने के नाते उन्हें प्रिंस और हिज रॉयल हाईनेस की उपाधि स्वतः प्राप्त थी।

सीएम योगी की बच्चों से अपील- स्मार्टफोन की जगह अच्छी पुस्तकों में करें अपने समय का निवेश

गोरखपुर, 1 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) परिसर में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। यह पुस्तक मेला 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) और डीडीयू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को पुस्तकें वितरित कीं और स्कूली विद्यार्थियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्ची साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। उन्होंने भारत की श्रवण परंपरा और गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे ऋषियों ने ज्ञान को लिपिबद्ध कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की अद्भुत परंपरा विकसित की। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक महोत्सव आने वाले 9 दिनों तक 200 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी रुचि की पुस्तकें खरीदने का शानदार अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं वेन सिटिजन, कंट्री लीड यानी जब नागरिक पढ़ते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर की भूमि इसलिए भी विशेष है क्योंकि पिछले 100 वर्षों से गीता प्रेस भारत और विश्व में सनातन धर्म की विचारधारा को अपनी पुस्तकों के माध्यम से पहुंचा रहा है। उन्होंने साहित्यकार फिराक गोरखपुरी, मुंशी प्रेमचंद, प्रो. विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे लेखकों का स्मरण किया और हाल ही में दिवंगत साहित्यकार श्रीराम दरस मिश्र को श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें हमेशा नई प्रेरणा देती हैं। हमें उनसे जुड़ना चाहिए। अगले 9 दिनों में यहां अनेक विमर्श, परिचर्चा, पुस्तकों के विमोचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ शहर की सभी संस्थाओं को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्यभर में पुस्तकालयों का जाल बिछा रही है। प्रदेश की 57,600 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों के साथ पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। 1.56 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में से 1.36 लाख विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है, जिनमें पुस्तकालय और डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों में पढ़ने की संस्कृति विकसित हो सके।

दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में एहसास करा रहा भारत - मुख्यमंत्री

गोरखपुर, 1 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी पहचान के संकट के दौर से गुजरने वाला भारत आज दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में एहसास करा रहा है। यह बदलाव लीडरशिप (नेतृत्व) की कार्यपद्धति से आया है। समर्थ और प्रभावी नेतृत्व वही होता है जो देश के प्रति दुनिया की धारणा बदलने का सामर्थ्य रखता हो। विगत 11 वर्षों से देश में ऐसी ही लीडरशिप देखने को मिल रही है।

सीएम योगी शनिवार को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सैमसंग इनोवेशन कैंपस द्वारा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के करीब 1300 छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से आठ विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2014 के पहले का भारत पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार व्यवस्था पर हावी था। वैश्विक स्तर पर देश का सम्मान समाप्त हो रहा था। युवा पहचान को मोहताज हो रहे थे। पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में विकास और

जनहित के अनेक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत पहचान स्थापित करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंडअप, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने भारत को न केवल नई पहचान दी है बल्कि देश को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनाने में भी भरपूर योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास किए गए।

सीएम योगी ने आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए युवाओं से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और नवाचार पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। कहा कि ईज ऑफ लिविंग (जीवन सुगमता) बढ़ाने में तकनीकी काफी सहायक हो सकती है। आज तकनीकी के इस्तेमाल से ऐसे नवाचार जरूरी हैं जिससे जीवन को और भी सहज और सरल बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने देश के विकास और जीवन सुगमता के लिए तकनीकी के महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) -2020 में भी महत्व दिए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में और सकारात्मक बदलाव लाने में एनईपी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है, बशर्ते सभी शिक्षण संस्थान इसे समयबद्ध ढंग से लागू करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनईपी के उद्देश्यों के अनुरूप टाटा टेक्नोलॉजी के साथ 150 से अधिक आईटीआई से युवाओं को मॉडर्न वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है सीएम योगी अपने संबोधन में विद्यार्थियों के समक्ष एक अभिभावक और शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था या सिस्टम को कोसना हममें से अधिकतर लोगों की आदत बन गई है। ऐसे लोगों को हर कार्य में सिर्फ सरकार दोषी लगती है। ऐसे लोग किसी समस्या पर अपनी खामी दूर करने की बजाय सिर्फ दूसरों की खामियों को निकालने में लगे रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समस्या असाध्य हो जाती है।

तुलसी के फायदे, उपयोग और औषधीय गुण

अक्सर भारतीय घरों में तुलसी का पौधा जरूर रखा जाता है, जहां इस पौधे की पूजा भी की जाती है. यहीं नहीं तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका हर एक हिस्सा काम का है. हिंदू घरों में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी को कई बीमारयों से लड़ने के लिए अच्छा उपचार माना जाता है. आईए ऐसे में जानते हैं क्या है

शास्त्रों और आयुर्वेद, दोनों में ही तुलसी के पौधे को घर में लगाने के कई लाभ बताएं गए हैं. यहां तक की पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है. जिसकी पूजा की जाती है. तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरफ से महत्व रखता है.

तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. सभी रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर इस औषधीय पौधे को प्रत्यक्ष देवी कहा गया है क्योंकि इससे ज्यादा उपयोगी औषधि मनुष्य जाति के लिए दूसरी कोई नहीं है. तुलसी के धार्मिक-महत्व के कारण हर-घर आगंन में इसके पौधे लगाए जाते हैं. तुलसी की कई प्रजातियां मिलती हैं. जिनमें श्वेत व कृष्ण प्रमुख हैं. इन्हें राम तुलसी और कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है.

कौन थीं तुलसी

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओगे. इसी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान ने शालीग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया शालीग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और तुलसी को मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है.

पने छल का प्रायश्चित करते हुए विष्णु जी ने खिले हुए पौधे को तुलसी का नाम दिया और कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जायेगा और तुलसी जी की पूजा के बगैर मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा. तुलसी जी को बहुत पवित्र माना जाता है.

भारत के अधिकांश घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। हमारे ऋषियों को लाखों वर्ष पूर्व तुलसी के औषधीय गुणों का ज्ञान था इसलिए इसको दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु इतनी प्रमुखत से स्थान दिया गया है। आयुर्वेद में भी तुलसी के फायदों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इस लेख में हम आपको तुलसी के फायदे, औषधीय गुणों और उपयोग के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

तुलसी क्या है?

तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर इस औषधीय पौधे को प्रत्यक्ष देवी कहा गया है क्योंकि इससे ज्यादा उपयोगी औषधि मनुष्य जाति के लिए दूसरी कोई नहीं है। तुलसी के धार्मिक-महत्व के कारण हर-घर आगंन में इसके पौधे लगाए जाते हैं। तुलसी की कई प्रजातियां मिलती हैं। जिनमें श्वेत व कृष्ण प्रमुख हैं। इन्हें राम तुलसी और कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। चरक संहिता और सुश्रुत-संहिता में भी तुलसी के गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन है। तुलसी का पौधा आमतौर पर 30 से 60 सेमी तक ऊँचा होता है और इसके फूल छोटे-छोटे सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं। इसका पुष्पकाल एवं फलकाल जुलाई से अक्टूबर तक होता है।

तुलसी का वानस्पतिक नाम Ocimum sanctum Linn. (ओसीमम् सेंक्टम्) और कुल का नाम (लैमिएसी) है। अन्य भाषाओं में इसे निम्न नामों से पुकारा जाता है।

औषधीय उपयोग की दृष्टि से तुलसी की पत्तियां ज्यादा गुणकारी मानी जाती हैं। इनको आप सीधे पौधे से लेकर खा सकते हैं। तुलसी के पत्तों की तरह तुलसी के बीज के फायदे भी अनगिनत होते हैं। आप तुलसी के बीज के और पत्तियों का चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं। इन पत्तियों में कफ वात दोष को कम करने, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने और रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं।

इसके अलावा तुलसी के पत्ते के फायदे बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियां, पेट दर्द, मलेरिया और बैक्टीरियल संक्रमण आदि में बहुत फायदेमंद हैं। तुलसी के औषधीय गुणों राम में तुलसी की तुलना में श्याम तुलसी को प्रमुख माना गया है। आइये तुलसी के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

दिमाग के लिए भी तुलसी के फायदे लाजवाब तरीके से काम करते हैं। इसके रोजाना सेवन से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और याददाश्त तेज होती है। इसके लिए रोजाना तुलसी की 4-5 पत्तियों को पानी के साथ निगलकर खाएं। ज्यादा काम करने या अधिक तनाव में होने पर सिरदर्द होना एक आम बात है। अगर आप भी अक्सर सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो तुलसी के तेल की एक दो बूंदें नाक में डालें। इस तेल को नाक में डालने से पुराने सिर दर्द और सिर से जुड़े अन्य रोगों में आराम मिलता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुलसी के उपयोग करने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आपके सिर में जुएं पड़ गये हैं और कई दिनों से यह समस्या ठीक नहीं हो रही है तो बालों में तुलसी का तेल लगाएं। तुलसी के पौधे से तुलसी की पत्तियां लेकर उससे तेल बनाकर बालों में लगाने से उनमें मौजूद जूं और लीखें मर जाती हैं। तुलसी के पत्ते के फायदे, तुलसी का तेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। कई लोगों को रात के समय ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, इस समस्या को रतौंधी कहा जाता है। अगर आप रतौंधी से पीड़ित हैं तो तुलसी की पत्तियां आपके लिए काफी फायदेमंद है। इसके लिए दो से तीन बूँद तुलसी-पत्र-स्वरस को दिन में 2-3 बार आंखों में डालें। अगर आप साइनसाइटिस के मरीज हैं तो तुलसी की पत्तियां या मंजरी को मसलकर सूघें। इन पत्तियों को मसलकर सूंघने से साइनसाइटिस रोग से जल्दी आराम मिलता है। तुलसी की पत्तियां कान के दर्द और सूजन से आराम दिलाने में भी असरदार है।

औषधीय उपयोग की दृष्टि से तुलसी की पत्तियां ज्यादा गुणकारी मानी जाती हैं। इनको आप सीधे पौधे से लेकर खा सकते हैं। तुलसी के पत्तों की तरह तुलसी के बीज के फायदे भी अनगिनत होते हैं। आप तुलसी के बीज के और पत्तियों का चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं। इन पत्तियों में कफ वात दोष को कम करने, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने और रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं।

मशरूम की खेती

सी.एम.शर्मा

मशरूम का उत्पादन युवाओं के लिए एक अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। मशरूम सेहत का रखवाला है, इसलिए मांग बढ़ रही है, पर आपूर्ति उतनी नहीं हो रही। ऐसे में यह व्यवसाय फायदे का सौदा है।डॉक्टर और डाइटीशियन मोटापा, हार्ट-डिजीज और डायबिटीज के रोगियों को इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। इसका चलन निरंतर बढ़ता जा रहा है।

भारत में मशरूम की मांग में इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए मशरूम के बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता है। वैसे तो मशरूम के उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जितनी मांग है, उसे देखते हुए वह बहुत कम है। हालांकि अब गांव ही नहीं, शहरों में भी शिक्षित युवा मशरूम उत्पादन को करियर के रूप में अपनाने लगे हैं।

मशरूम की खेती को छोटी जगह और कम लागत में शुरू किया जा सकता है और लागत की तुलना में मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है।

यहाँ तक की इसे आप एक कमरे में भी शुरू कर सकते है ।सालभर में आप सिर्फ एक कमरे में 3 से 4 लाख रुपए की इनकम आसानी से हो सकती है वह भी सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए खर्च करने के बाद

मौसम

मशरूम उत्पादन में मौसम का खास महत्व है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मशरूम की एक वैराइटी वॉल वैरियल्ला के लिए तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस व नमी 80 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका उत्पादन अप्रैल से अक्टूबर के बीच किया जाता है। ऑयस्टर मशरूम के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा नमी 80 फीसदी से अधिक होनी चाहिए। इसके उत्पादन के लिए सितम्बर-अक्टूबर का महीना बेहतर माना जाता है। टेम्परेंट मशरूम के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व 70 से 90 फीसदी नमी जरूरी है। इसका उत्पादन अक्टूबर से फरवरी के बीच ठीक रहता है।

ओएस्टर मशरूम की खेती इस मशरूम को उगाने में गेहूं के भूसे और दानों दोनों का इस्तेमाल होता है। यह मशरूम 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। ज्यादातर इसका उत्पादन पंजाब समेत उत्तर भारतीय राज्यों में होता है। इस मशरूम को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनंत कुमार ने साल 2013 में उगाया था। प्रोफेसर अनंत कुमार अपनी इस विधि का अब पेटेंट कराने जा रहे हैं।

100 वर्गफीट के कमरे से 10 क्विंटल मशरूम

प्रो. अनंत कुमार के अनुसार एक किलोग्राम मशरूम को तैयार करने में लगभग 50 रुपए का खर्च यदि भूसा, गेहूं आदि सब सामान खरीदा जाए आता है।

इसके तहत 15 किलोग्राम मशरूम बनाने के लिए 10 किलोग्राम गेहूं के दानों की आवश्यकता होती है। यदि आप एक बार में 10 क्विंटल मशरूम उगा लेते हैं तो आपका कुल खर्च 50 हजार रुपए आता है। इसके लिए आपको 100 वर्गफीट के एक कमरे में रैक जमानी होगी।

10 ग्राम लगता है बीज

सबसे पहले गेहूं को उबाला जाता है और इस पर मशरूम पाउडर डाला जाता है, जिससे मशरूम का बीज तैयार हो जाता है। इसे तीन महीने के लिए इस बीज को 10 किलोग्राम गेहूं के भूसे में 10 ग्राम बीज के हिसाब से रखा जाता है। 3 महीने बाद गेहूं के ये दाने मशरूम के रूम में अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें 20 से 25 दिनों के लिए पॉलिथीन में डालकर 25 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान वाले कमरे में रखा जाता है। इसके बाद मशरूम बिकने के लिए तैयार होता है।

रीटेल स्टोर से कर सकते हैं करार ओइस्टर मशरूम की देश में सबसे अधिक मांग है। ब्रांडेड स्टोर पर भी सबसे ज्यादा ओइस्टर मशरूम ही बिकता है। इस मशरूम के दाम कम से कम 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम मिलते हैं। यदि आप बेहतर मार्केटिंग कर किसी रिटेल स्टोर से करार कर सकते हैं तो दाम और भी बेहतर मिल सकते हैं। कम से कम 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 क्विंटल मशरूम की कीमत 150000 रुपए होती है। ऐसे में मशरूम साल में दो बार पैदा किया जाए तो यह रकम आसानी से दोगुनी यानी 3 लाख रुपए तक पहुंच जाती है।

सरकारी सहायता

मशरूम उत्पादन स्वरोजगार के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है। यह काम कम पूंजी और छोटी जगह पर भी हो सकता है। सरकार कृषि से संबंधित इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने वाले उम्मीदवारों को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा एससी/एसटी उम्मीदवारों को सरकारी ऋण में राहत की भी व्यवस्था है।

मशरूम उत्पादन में रुचि लेने वाले उम्मीदवारों के लिए देशभर के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों व कृषि अनुसंधान केंद्रों में एक से दो हफ्ते और मासिक अवधि के कोर्स संचालित किए जाते हैं।

इन पाठय्क्रमों का उद्देश्य मशरूम उत्पादन की तकनीक व बीजों की अच्छी नस्ल से रू-ब-रू कराना है। मशरूम का उत्पादन शुरू करने से पहले तकनीकी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है।

संरक्षित खेती का महत्व

संरक्षित खेती का मतलब होता है खेती करने का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका जिसके अर्न्तगत पौधों को विपरीत प्रकृतिक परिस्थितियों या प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, तेज सर्दी, तेज हवा, तेज प्रकाश की तीव्रता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि से पौधों का बचाव किया जाता है पौधों को संरक्षण दिया जाता है और उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है जो कि उनकी बढ़वार में सहायक होती है और इस तरीके से उनसे अच्छी गुणवत्ता की और ज्यादा पैदावार प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से जो खेती की जाती है उसे हम संरक्षित खेती कहते हैं।

संरक्षित खेती के अंतर्गत कई कृत्रिम संरचनाएं बनानी पड़ती हैं जैसे पॉलीहाऊस, शेडनेट हाऊस, ग्लास हाऊस, वाक-इन टनल, लो टनल इत्यादि। इन संरचनाओं के अंदर तापमान, आर्द्रता वायु का बहाव, प्रकाश की तीव्रता और सी.ओ.टू (कार्बन डाय आक्साईड) का स्तर काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और पौधे की बढ़वार में सहायक सभी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार से जो खेती की जाती हैं उसे संरक्षित खेती कहते हैं।

अगर हम ग्रीन हाऊस के बारे में बात करें तो ग्रीन हाऊस लोहे की पाईपों से बना एक ऐसा घर है जो कि पारदर्शी आवरण से ढका रहता है। अगर ये पारदर्शी आवरण पॉलीथिन है तो इसे हम पॉली हाऊस कहते हैं

पॉली हाऊस का इस्तेमाल आमतौर पर कट फ्लावर की खेती यानि डंडी वाले फूलों की खेती के लिए किया जाता है और डंडी वाले फूल जो लगाये जा सकते हैं वो हैं डच्च गुलाब, जरबेरा और कुछ जगहों पर हम कारनेशन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बेमौसमी सब्जियों की खेती भी पॉली हाऊस में की जा सकती है।

शेडनेट के बारे में कहा जाता है शेडनेट लोहे की पाईपों से बना ऐसा ढांचा होता है जो कि हरे रंग की या सफेद रंग की जाली से या शेड नेट से ढ़का होता है। उसे हम शेडनेट करते हैं। शेडनेट हाऊस के अर्न्तगत हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं बेमौसमी सब्जियाँ लगा सकते हैं बेल वाले टमाटर, हरी, लाल, पीली, बैंगनी, नारंगी रंगों वाली शिमला मिर्च, धनियां, बीज रहित खीरा इत्यादि।

सबसे अच्छा व्यवसाय तो नर्सरी का व्यवसाय है जिसको की आप शेडनेट हाऊस के अन्दर कर सकते हैं। इसके अन्दर आप सब्जियों की पौध भी तैयार कर सकते हैं उसके लिए आप को चाहिए प्लास्टिक की प्रो ट्रे या नर्सरी ट्रे जिसमें की लगभग अठयानवें छेंद होते हैं उन छेदों के अन्दर कोको पिट एवं वर्मीकम्पोस्ट भरा जाता है और कोको पिट भरने के पश्चात उनमें एक-एक बीज लगा दिया जाता है इस तरीके से पौध तैयार की जाती है टमाटर की पौध तैयार होने में लगभग 25 से 28 दिन लगते हैं। शिमला मिर्च या हरी शिमला मिर्च की पौध तैयार करने में 35 से 40 दिन लगते हैं और वैसे ही अगर आप खीरे की पौध तैयार करना चाह रहे हैं सर्दियों के अन्दर, तो सर्दियों में लगभग आप को 20 से 21 दिन लगते हैं और गर्मियों में यह 15 से 18 दिन में तैयार हो जाती है।

'लो टनल' लो टनल का मतलब होता है छोटी सुरंगनुमा संरचना या एक ढ़ाचा जो कि छोटा सुरंगनुमा आकार का होता है खासतौर से इसको बनाया जाता है लगभग जब तेज सर्दियां पड़ती हैं दिसम्बर, जनवरी माह में (15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक) इसको बनाया जाता है और पहले एक मीटर की बेड बनाई जाती है जो की ऊपर से 90 से.मी. होती है और उसके ऊपर यू शेप या अर्द्धचन्द्राकार में पाईप या लोहे का तार लगा दिया जाता है प्लास्टिक की पाईप या मोटा तार बेन्ड करके लगा दिया जाता है और उसको हर ढाई से तीन मीटर की दूरी पर लगाया जाता है।

इसे हुप्स कहा जाता है और इन हुप्स को ऊपर से पॉलीथिन से ढ़क दिया जाता है और उसके अन्दर खेती की जाती है। पॉलिथिन के स्थान पर नोन वोवन प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इसमे छेद करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह की खेती जो कि लो टनल के अन्दर की जाती है ये आमतौर पर सर्दियों में की जाती है।

कुछ सब्जियां या फसलें होती हैं जो उग नहीं पाती सर्दियों की वजह से परन्तु इस तरीके की सुरंगनुमा लो टनल बनाकर उसके अन्दर अच्छी तरह से ना केवल उगाई जा सकती है बल्कि अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद एवं ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है जिनका बाजार में अच्छा भाव मिलता है जैसे खासतौर से बेल वाली फसलें जैसे छप्पन कद्दू, टिन्डा, खरबूजा, तरबूज इत्यादि आमतौर पर लगाये जाते हैं और इनसे अच्छे बाजार भाव प्राप्त होते हैं और इस तरह की जो लो टनल होती हैं इनकी ऊंचाई एक सवा मीटर की होती है और इसके अन्दर व्यवसायिक खेती की जा सकती है और इसका चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है।

संरक्षित खेती आज हमारे किसान भाईयों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है और किसान भाई इसे अपना कर ना केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं बल्कि समाज में अच्छा नाम, अच्छी इज्जत और अपनी अच्छी पहचान बना रहे हैं।

युवा वर्ग भी इस प्रकार के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती के प्रति आकृषित हो रहा है और खेती से जो उनका मौह पूर्व में भंग हो गया था। वह मौह वापस पैदा हो रहा है और वह खेती के प्रति आकृषित हो रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं।

पिछले कुछ सालों में किसान भाईयों ने मल्च का प्रयोग करना भी खेती में चालू कर दिया है। मल्च का मतलब होता है प्लास्टिक की एक पतली फिल्म जिसको की उठी हुई क्यारियों पे बिछा दिया जाता है। इसके अपने फायदे हैं। मल्च वैसे तो कई रंगों में आती है।

मल्च के अपने कुछ फायदे हैं

1. पहला, इससे पौधे के आस पास खरपतवार नहीं उगती है जिससे आपको अतिरिक्त मजदूर या मेहनत नहीं लगानी पड़ती है

2. दूसरा, पानी का संरक्षण होता है, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता और नमी ज्यादा समय तक रहती है,

3. तीसरा, जो सिल्वर रंग की परत ऊपर की तरफ है तो उस पर सूर्य की किरणें गिरती हैं और दर्पण के रूप में परावर्तित हो जाती हैं और ये किरणे परावर्तित होकर मल्च से निचले पत्तों पर निचली तरफ पड़ती है जिससे वहाँ पर किसी प्रकार के कीट-पतंगे उस प्रकाश के कारण वहां रह नहीं पाते और वहां से जाने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार से सिल्वर रंग के मल्च का प्रयोग करते हैं तो कीट-पतंगों का प्रकोप भी कम होता है।